वर्षः 5 अंकः 17

1-15 मार्च, 2025 (निःशुल्क)

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) विशेष

न्यू इंडिया समाचार

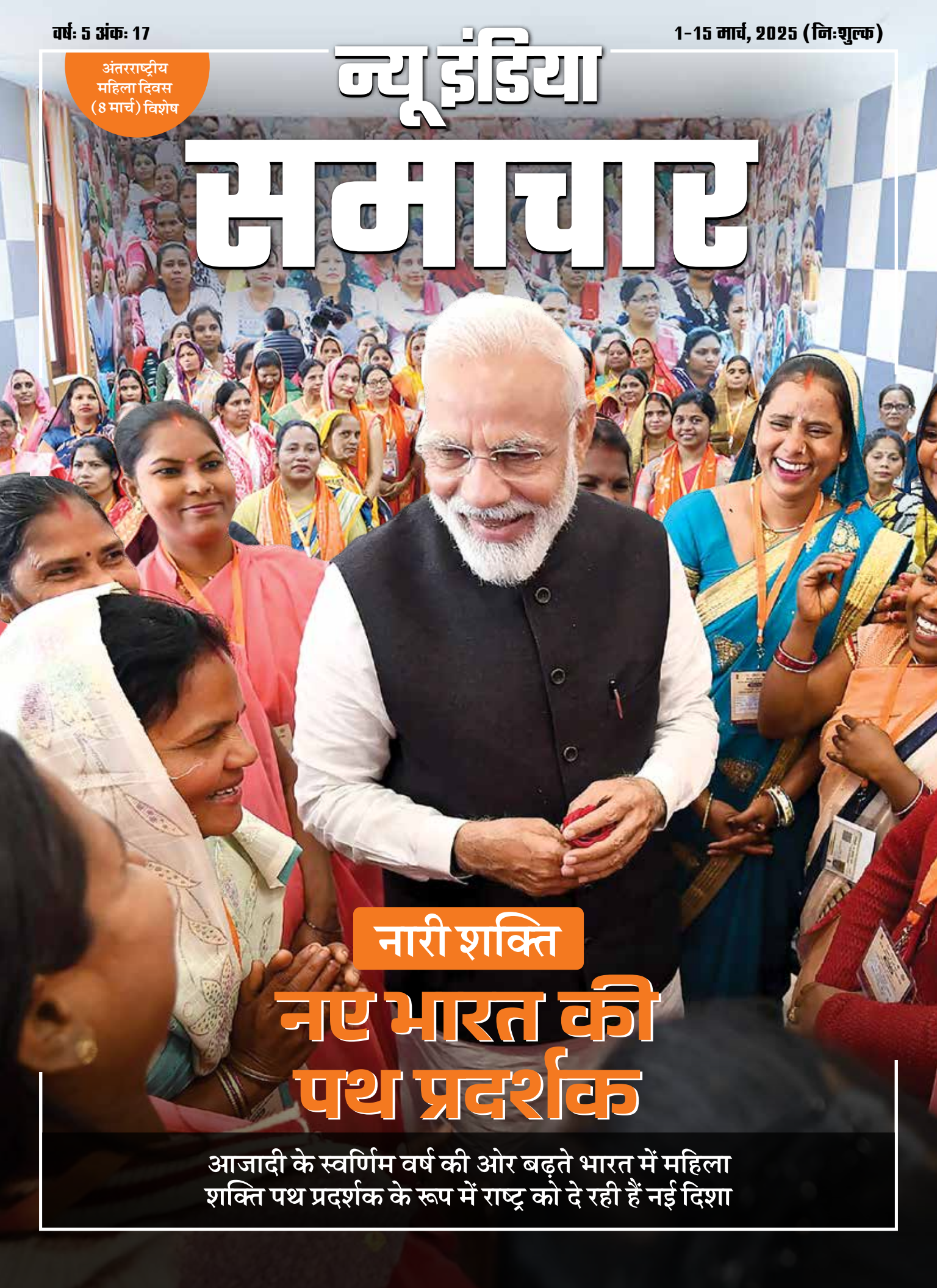

नारी शक्ति

नए भारत की पथ प्रदर्शक

आजादी के स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत में महिला शक्ति पथ प्रदर्शक के रूप में राष्ट्र को दे रही हैं नई दिशा

दांडी आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव

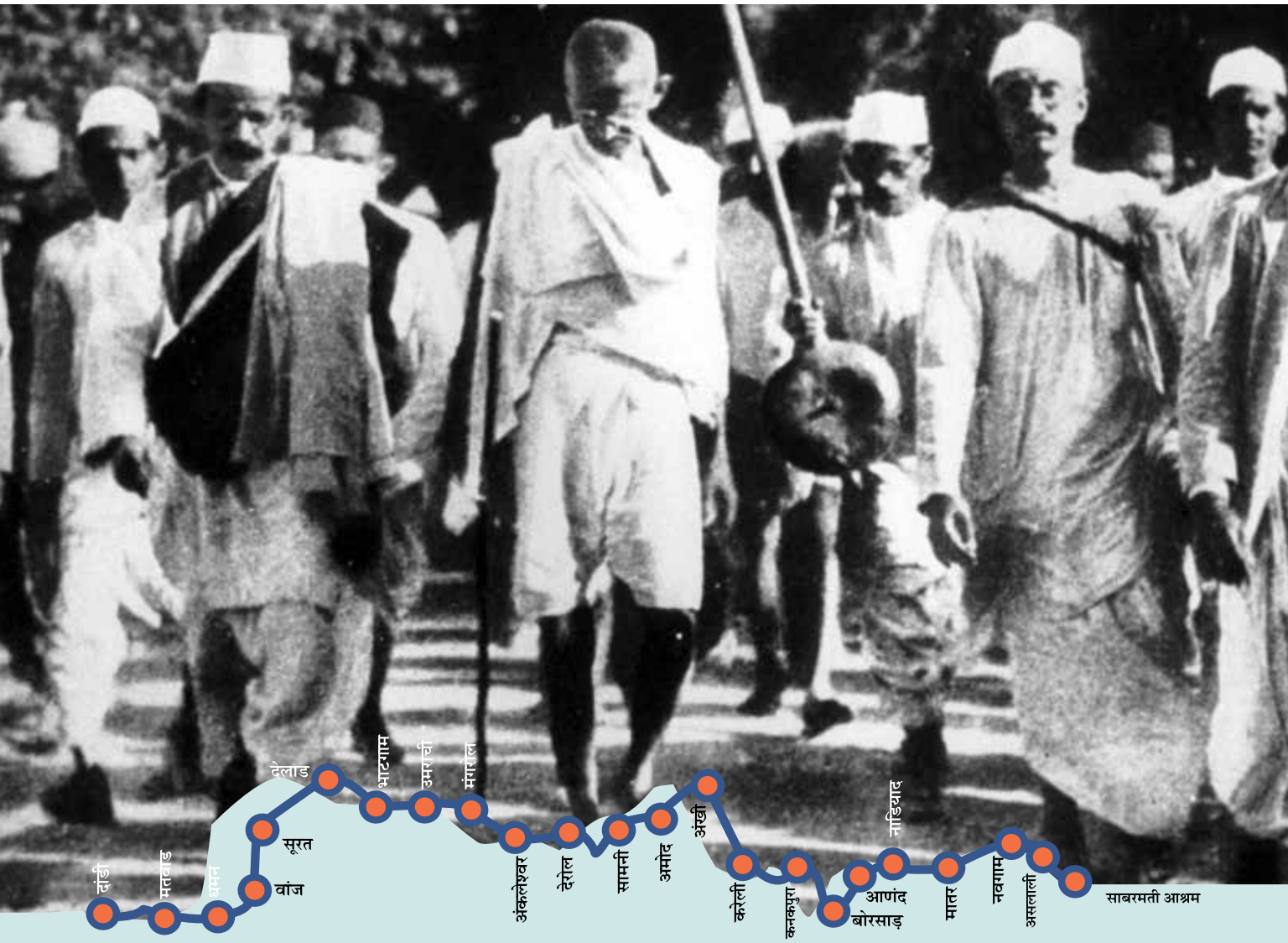

नमक कानून के विरोध में निकाले गए दांडी मार्च का इस वर्ष 12 मार्च को 95 साल पूरे हो रहे हैं। इस मार्च के जरिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस सत्ता को चुनौती दी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। यह यात्रा गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी तक गई थी। दांडी मार्च को माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव...

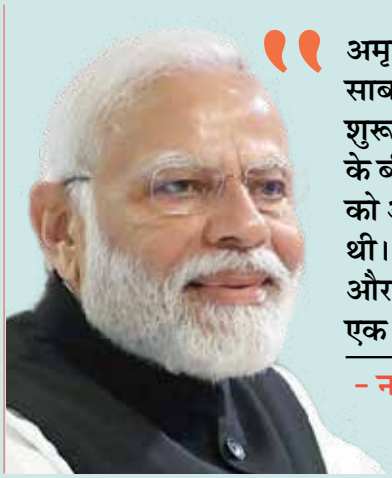

अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ था। उस पदयात्रा ने भारत के लोगों के बीच गर्व और आत्मनिर्भरता की भावना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की थी। 'वोकल फॉर लोकल' को अपनाना बापू और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक अद्भुत श्रद्धांजलि है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया
समाचार

वर्षः 5, अंकः 17 । 1-15 मार्च, 2025

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

चीफ डिजाइनर
श्याम तिवारी

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होगी और उसमें लगभग 75 करोड़ आबादी महिला शक्ति की होगी। अगर उन्हें समुचित अवसर मिले तो भारत दोगुनी गति से आगे बढ़ सकता है। इसी दृष्टिकोण के साथ आधी आबादी के सामर्थ्य की पहचान कर बीते एक दशक में सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक रूप से सशक्त करने की हुई है पहल... | 12-25

"जो विषय डराए, पहले उसी से निपटें"

इस आयोजन में अनौपचारिक बातचीत में पीएम मोदी ने छात्रों के साथ कई विषयों पर की चर्चा | 7-11

विकसित भारत की तस्वीर 'बचत भी, विकास भी' मॉडल

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में पीएम मोदी ने 10 साल के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया | 26-29

समाचार सार | 4-5

व्यक्तित्व - मेजर संदीप उन्नीकृष्णन
मुंबई 26/11 के हमले में आतंकियों से लोहा लेते वीरगति को प्राप्त हुए | 6

इंडिया एनर्जी वीक : विकसित भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र अहम
विकास को बढ़ावा देने के साथ प्रकृति को समृद्ध कर रहा भारत | 30-31

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन
सुलभता और समावेशिता को बढ़ावा | 32-34

भारत टेक्स : विकसित भारत की संभावनाओं का दर्शन
भारत मंडपम में भारत टेक्स- 2025 में 120 से अधिक देशों ने की शिरकत | 40-41

विकसित भारत की असली नींव है विश्वास
ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी का संबोधन | 42-43

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय
कौशल भारत कार्यक्रम को दो साल का विस्तार | 44

अमेरिका-फ्रांस दौरा

पीएम मोदी ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ मेक इंडिया ग्रेट को जोड़ते हुए नेशन फर्स्ट को सबसे आगे रखा...

भारत-फ्रांस का मजबूत होता रणनीतिक सहयोग... | 35-39

प्रकाशक और मुद्रकः योगेश कुमार बवेजा, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **मुद्रणः** जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020। **पत्राचार और ईमेल के लिए पताः** कमरा संख्या-316, नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001। **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

नए भारत के विकास चक्र में बढ़ी नारी शक्ति की भागीदारी

सादर नमस्कार।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2025 की आप सभी को शुभकामनाएं। यह निर्विवादित सत्य है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। ऐसे में महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि सामाजिक विकास के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। इस दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार ने देश के भीतर महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2014 से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत कर हर चरण में उनके लिए विशेष नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं ताकि न केवल नारी शक्ति का विकास हो, बल्कि नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास नए भारत की आधारशिला बने।

नए भारत के विकास चक्र में महिलाओं की भागीदारी निरंतर रूप से बढ़ रही है। नारी जब कोई जिम्मेदारी संभालती है तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वह जी-जान से जुट जाती हैं। ऐसे में अब अमृत काल में नारी शक्ति का अभ्युदय सुनिश्चित हो, इसके लिए सशक्तीकरण की इस यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाना सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार की सोच है कि नारी शक्ति के प्रति सम्मान के दृष्टिकोण का उद्देश्य केवल एक प्रतीक न हो, बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित हो, ताकि वह भारत की समृद्धि की यात्रा में सक्रिय रूप से भागीदार बन सकें।

भारत की विकास यात्रा, देश की महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध की पहचान करते हुए, केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में नारी शक्ति को अपने एजेंडे में सर्वोपरि रखा है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि नारी शक्ति आज नए भारत की पथ प्रदर्शक बनकर उभरी हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यही हमारी आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, छात्रों का मनोबल बढ़ाने वाली परीक्षा पे चर्चा, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब इसमें शामिल है। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और फ्रांस की यात्रा सहित पखवाड़े भर के उनके अन्य कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। पत्रिका के इनसाइड पेज पर 12 मार्च को दांडी मार्च की वर्षगांठ पर विशेष सामग्री और बैक कवर पर 3 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व वन्यजीव दिवस को समाहित किया गया है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

धीरेन्द्र

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

उपलब्धि और विकास के बारे में मिलती है अमूल्य जानकारी

छात्रों को सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए न्यू इंडिया समाचार पत्रिका काफी उपयोगी है। यह पत्रिका राष्ट्रीय नीति, सरकार की उपलब्धि और विकास के बारे में अमूल्य जानकारी एवं अपडेट प्रदान करता है जो छात्रों के लिए मददगार साबित होती है।

धनराज उमापति

bharathipayilagamiasacademy@gmail.com

पत्रिका में मिलती है उपयोगी और तथ्यपरक जानकारी

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका के कुछ पन्ने मुझे अपने दोस्त के मोबाइल पर पढ़ने को मिले। इसमें काफी उपयोगी और तथ्यपरक जानकारी दी गई थी। यह मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। मैं इस पत्रिका का नियमित पाठक बने रहना चाहता हूं।

अभिषेक कुमार

abhishekkumar108005@gmail.com

प्रशिक्षण और सामुदायिक विकास में उपयोगी पत्रिका

मैंने हाल ही में एक एनजीओ पंजीकृत कराया है। न्यू इंडिया समाचार पत्रिका बहुत बेहतरीन है। इसमें दी गई जानकारी हमारे लिए प्रशिक्षण और सामुदायिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है। मेरे संस्थान और यहां आने वाले लोगों में इस पत्रिका को लेकर काफी दिलचस्पी है।

aswaddilipingle@gmail.com

देश को जोड़ती, ऊर्जा प्रदान करती न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

मुझे आपकी पत्रिका न्यू इंडिया समाचार पढ़ने को मिली। इसमें प्रकाशित विभिन्न आलेखों के माध्यम से मुझे बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों से मैं अवगत हुआ। यह पत्रिका अपने देश से जोड़ती है, ऊर्जा प्रदान करने के साथ- साथ उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।

sharmakrishna58668@gmail.com

सम-सामयिक घटनाओं से अवगत कराती न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका के माध्यम से सभी सम-सामयिक घटनाओं से अवगत होता हूं। मैं सरकार द्वारा दी जाने वाली हर योजना के बारे में विस्तार से जान पाता हूं। मैं अपने कार्यालय और अन्य जगहों पर लोगों के साथ उन सभी जानकारियों को साझा भी करता हूं। यह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस पत्रिका के माध्यम से अभ्यर्थियों को भारत के विकास और प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने काफी मदद मिलती है।

manishkhandelwal002@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-316,
नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी पर सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

समाचार सार

जम्मू-कश्मीर में जीरो टेरर प्लान के लिए ठोस कदम

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसफ को कड़ी निगरानी, बॉर्डर ग्रिड को मजबूत करने के साथ ही निगरानी और सीमा सुरक्षा के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 'जीरो घुसपैठ' सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आतंक-वित्त पोषण की निगरानी, नार्को-आतंकवादी मामलों पर कड़ी पकड़ और जम्मू-कश्मीर में पूरे टेरर इकोसिस्टम को खत्म करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। जम्मू-कश्मीर में जीरो टेरर प्लान के लिए मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए तालमेल के साथ काम जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है।

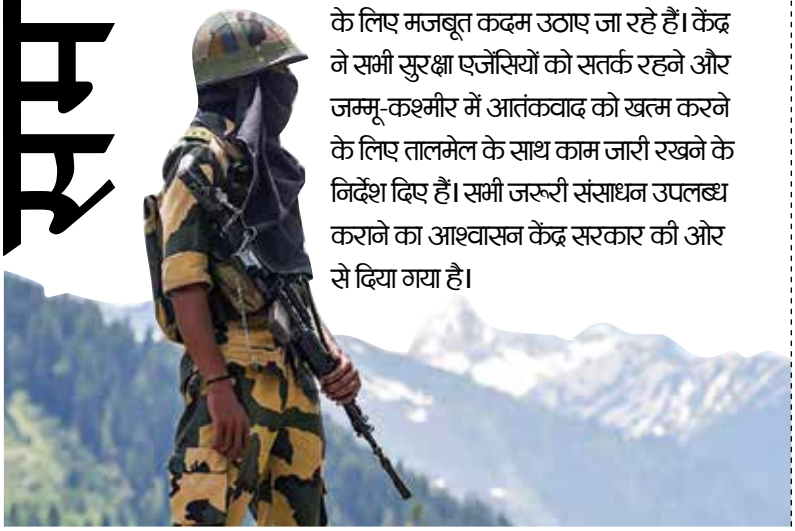

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन से भारत वैश्विक निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन का बड़ा योगदान है। वर्ष 2014 में जहां मोबाइल उत्पादन की दो इकाई थी वह अब बढ़ कर 300 से अधिक हो गई है। 2014-15 में भारत में बिकने वाले सिर्फ 26% मोबाइल फोन यहां बनते थे बाकी आयात किए जाते थे। वहीं आज देश में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बन रहे हैं। वर्ष 2014 में मोबाइल फोन निर्माण का मूल्य 18,900 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2024 में बढ़कर 4.22 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 2014 में निर्यात न के बराबर था जो अब बढ़ कर 1.29 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। मोबाइल कारोबार ने देश में पिछले दशक में लगभग 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं।

त्रिवेणी एल्बम के लिए चंद्रिका कृष्णमूर्ति को ग्रैमी अवॉर्ड

भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन ने संगीत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ग्रैमी पुरस्कार जीतकर एक बार फिर से सनातन संस्कृति का पूरी दुनिया में मान बढ़ाया है। जब देश में महाकुम्भ का आयोजन चल रहा था ठीक उसी समय अमेरिका के लॉस एंजेलिस में ग्रैमी अवॉड समारोह (संगीत महाकुम्भ) चल रहा था। इस आयोजन में चंद्रिका को वैदिक मंत्रों से लबरेज त्रिवेणी एल्बम के लिए यह पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगीतकार चंद्रिका टंडन को एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनके अनुराग, उद्यमी, परोपकारी और संगीतकार के रूप में पीएम मोदी ने उनकी उपलब्धियों की सराहना की।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से अब ले सकेंगे पेट्रोल और डीजल

सरकार ने सहकारी क्षेत्र में अपनी भूमिका का विस्तार करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को खुदरा पेट्रोल और डीजल आउटलेट के साथ-साथ एलपीजी वितरण संचालित करने की अनुमति दी है। इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नियमित और ग्रामीण खुदरा दुकान डीलरों के चयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 286 पैक्स ने पेट्रोल, डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए जिनमें से ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 26 पैक्स का चयन किया है।

पैक्स को व्यवहार्य बनाने के लिए बनाए गए बायलॉज की वजह से इन समितियों को अभी तक 20 से अधिक गतिविधियों से जोड़ा जा चुका है। अब वे कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र, रेलवे टिकट की बुकिंग सहित अन्य सेवाएं प्रदान करना

शुरू कर चुकी हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विश्वास जताया है कि जल्द ही पैक्स भी एयरलाइंस टिकटों की बिक्री कर सकेंगे।

पीएम सूर्य घर: एक वर्ष में 8.46 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला लाभ

पीएम सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना है। इसने भारत की सौर क्रांति को सशक्त बनाते हुए सफलतापूर्वक एक वर्ष पूरा किया है। योजना से छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना से 27 जनवरी, 2025 तक, छत पर सौर ऊर्जा लगाने पर 8.46 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले सबसे अधिक परिवार वाले शीर्ष 5 राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान शामिल है। मार्च 2027 तक योजना का विस्तार एक करोड़ घर तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

कौशल विकास के क्षेत्र का विस्तार करेगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास पर निरंतर फोकस रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने हाल ही में देश भर में कौशल विकास अवसरों के विस्तार का निर्णय लिया है। कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए 50 नए भविष्य कौशल केंद्र और 10 एनएसडीसी अंतरराष्ट्रीय अकादमी स्थापित करने की योजना है। उद्योग की जरूरत के हिसाब से 300 से ज्यादा प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिसमें 12 प्रमुख उभरती हुई टेक्नोलॉजी को कवर किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के साथ 2.70 लाख वर्ग मीटर में प्रशिक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का है।

वैश्विक मनोरंजन केंद्र बनेगा भारत

भारत सरकार लगातार क्रिएटिविटी और नई विधाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मनोरंजन, रचनात्मकता और संस्कृति की दुनिया को एक साथ लाने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) के सलाहकार बोर्ड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों ने न सिर्फ अपना समर्थन दोहराया बल्कि भारत को वैश्विक मनोरंजन केंद्र बनाने के प्रयासों को और आगे बढ़ाने के तरीके पर भी बहुमूल्य सुझाव साझा किए।

वेव्स का मुख्य आकर्षण क्रिएट इन इंडिया चैलेंज है, जिसके लिए 70,000 से अधिक प्रतिभागियों ने आवेदन भेजे हैं। इसके प्रमुख कार्यक्रमों में एनिमेशन फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता, ट्रेलर सृजन प्रतियोगिता, वेव्स 2025 लाइव प्रसारण में गलत सूचना से निपटने के लिए एआई-संचालित समाधान पेश करना, 'रील मेकिंग' चैलेंज, वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैम्पियनशिप सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। दुनिया भर के देशों से इन कार्यक्रमों में हजारों भागीदारी मिली। ■

ऊपर मत आना, मैं उनसे निपट लूंगा

भारतीय सेना को अदम्य शौर्य और साहस का प्रतीक माना जाता है तो इसकी वीर गाथाओं में बलिदान के वह उदाहरण भी हैं जो खुद को होम कर राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन गए। त्याग और बलिदान के ऐसे ही प्रतीक हैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन... जिन्होंने सेना में कमान संभालते ही कारगिल में दुश्मनों के दांत खट्टे किए तो मुंबई में 26/11 के हमले में आतंकियों को खदेड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया...

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई 26-27 नवंबर 2008 को जब कायराना आतंकी हमलों से जूझ रही थी, होटल ताज में मेजर संदीप एक टीम को साथ लेकर फंसे हुए लोगों को बचा रहे थे। 10 कमांडो की टीम के साथ वे होटल में घुसे और आतंकवादियों पर गोलियों की बौछार कर दी। अपने एक साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उन्होंने आतंकियों का पीछा किया। आतंकवादी उनके डर से दूसरे फ्लोर पर भाग गए। लगातार फायरिंग के बीच में जब वे कुछ लोगों को बचा रहे थे, तब एक आतंकवादी ने पीछे से उनके ऊपर लगातार गोलियां चलाई। इस हमले में संदीप बुरी तरह घायल हुए और उन्होंने वीरगति प्राप्त की। तिरंगे में लिपटा मेजर उन्नीकृष्णन का पार्थिव शरीर जब बंगलौर लाया गया था तो उनके परिजन, मित्र और बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस जांबाज को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी थी।

वीरगति प्राप्त करने से पहले मेजर संदीप ने न सिर्फ अपने साथियों को बचाया, बल्कि उन्हें रोकते हुए कहा, "ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा।" उनके असाधारण साहस और नेतृत्व ने उनके साथियों को सभी आतंकवादियों को खत्म करने और सौंपे गए मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें 26 जनवरी 2009 को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।

केरल के कोझिकोड में 15 मार्च 1977 को पैदा हुए संदीप उन्नीकृष्णन एक ऐसे बहादुर सिपाही थे, जिन्होंने एनडीए में अपने शुरूआती दिनों में ही एक अलग पहचान बनाई थी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 6 सैनिकों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए बिहार रेजीमेंट के उन्नीकृष्णन ने दुश्मन की एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर विजय हासिल की थी। बिहार रेजीमेंट के अधिकारी मेजर उन्नीकृष्णन ने जून 1999 में भारतीय सेना में कमीशन हासिल किया था और जनवरी 2007 में उन्हें एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का ट्रेनिंग कमांडर बना दिया गया।

इसरो में कार्यरत उनके पिता ने उन्नीकृष्णन के बारे में एक बार अपने एक संस्मरण में बताया था कि संदीप हमेशा चाहते थे कि हमारा देश जीते। जब भारत कोई मैच हारता था तो वह बहुत निराश हो जाते थे। जब भी इसरो की कोई परियोजना विफल होती थी तो वह मुझे सांत्वना देता था। उसे हार पसंद नहीं थी। संदीप अपने किसी सहकर्मी के शव पर किसी मां को रोते हुए नहीं देखना चाहते थे। यही कारण है कि वह अक्सर कहते थे कि उनकी मां भी न रोए और इस दुख को सहन करे। ■

8वां संस्करण

परीक्षा पे चर्चा 2025

नहीं सताएगा परीक्षा का डर

"जो विषय डराए, पहले उसी से निपटें"

परीक्षाएं अक्सर छात्र और उनके परिवार के लिए तनाव का कारण बन जाती हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस नैरेटिव को बदलता जा रहा है। प्रत्येक संस्करण में परीक्षा से संबंधित चिंता से निपटने के लिए अभिनव तरीकों पर रोशनी डाली जाती है। इसी कड़ी में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण का आयोजन 10 फरवरी को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया। इस आयोजन में अनौपचारिक बातचीत में पीएम मोदी ने छात्रों के साथ कई विषयों पर की चर्चा...

बंद कमरे से हट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिल्ली के सुंदर नर्सरी के खुले वातावरण में छात्रों के साथ एक घंटे तक परीक्षा पे चर्चा की। 5 करोड़ से अधिक भागीदारी के साथ, इस वर्ष का कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में सामने आया। इस वर्ष, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 36 छात्रों का चयन सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सीबीएसई और नवोदय विद्यालयों से किया गया। परीक्षा पे चर्चा 2025 के माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वारियर्स को उत्साह और बिना किसी डर के सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। परीक्षा पे चर्चा का नया संस्करण परीक्षा के तनाव से बेहतर ढंग से निपटने के तरीके बताता है और गहन

8वां संस्करण

परीक्षा पे चर्चा 2025

2018 : पहली बार हुई बातचीत

परीक्षा पे चर्चा 16 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 2,500 से अधिक विद्यार्थी मौजूद थे और देश भर के 8.5 करोड़ से अधिक छात्र कार्यक्रम से जुड़े।

2019

बढ़ती पहुंच

29 जनवरी, 2019 को परीक्षा पे चर्चा का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें भागीदारी का स्तर और भी अधिक बढ़ा। नब्बे मिनट से अधिक समय तक चली इस बातचीत में छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए।

2020

भागीदारी का विस्तार

20 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए 2.63 लाख प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। भारत सहित विश्व के 25 देश से छात्रों ने इसमें भाग लिया।

2021

वर्चुअल संपर्क

कोविड-19 महामारी के कारण, पीपीसी का चौथा संस्करण 7 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया।

2022

आमने-सामने बैठकर बातचीत करने की वापसी

1 अप्रैल 2022 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। 9,69,836 छात्र, 47,200 कर्मचारी और 1,86,517 अभिभावक ने सीधा प्रसारण देखा।

अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) कार्यक्रम में छात्रों से कहा कि विफलताओं को अपना शिक्षक बनाना चाहिए। जीवन सिर्फ परीक्षा नहीं है। फेल होने से जीवन रुकता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने परीक्षा से संबंधित तनाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का काम किया है। इस कार्यक्रम ने छात्रों को दबाव में रहकर भी अच्छा करने और उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। समावेशिता, डिजिटल पहुंच और अभिनव तरीके इस कार्यक्रम की निरंतर सफलता सुनिश्चित करते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हर साल इस संदेश को और मजबूती प्रदान करता है कि परीक्षाएं अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत हैं। छात्रों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें तिल से बनी मिठाइयां भी वितरित कीं।

मैथमेटिक्स, अरे तू समझता क्या है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ बातचीत में कहा कि हमारा जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम उसी में टाइम लगा देते हैं। जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको हाथ तक नहीं लगाते हैं। जबकि, हमें चैलेंज करना चाहिए। यह समझता क्या है, यह ज्योग्राफी के दिमाग में क्या भरा है। यह ज्योग्राफी मेरे शरण में क्यों नहीं आ रही है। मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूंगा। ऐसे मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक्स, अरे तू समझता क्या है। आजा, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। मन में मुझे विजेता होना है, मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी है, मुझे झुकना नहीं है, का एक भाव होना चाहिए।

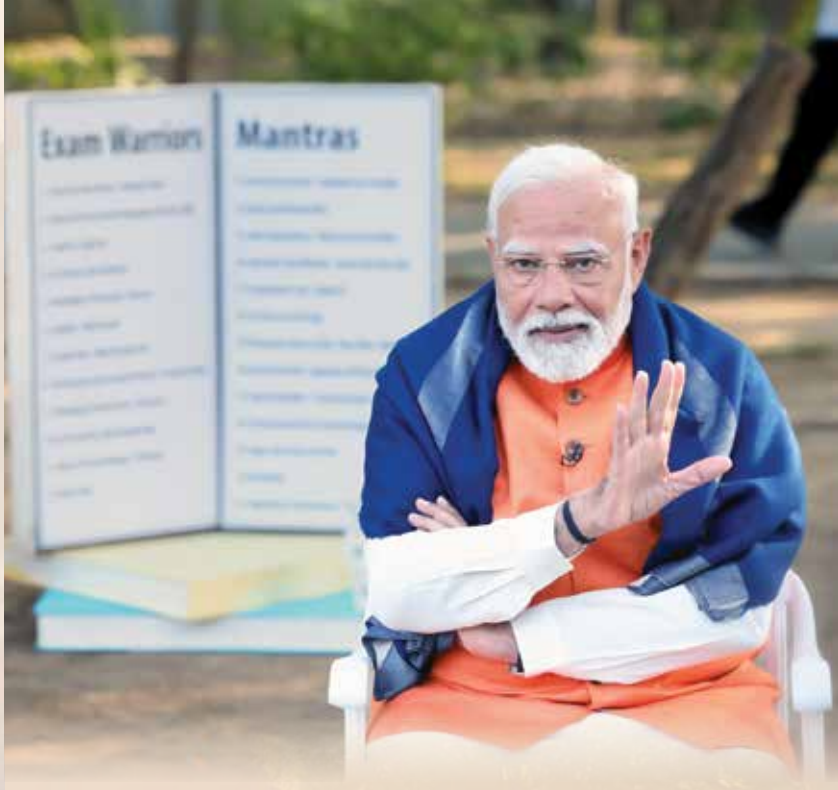

2023 भागीदारी का विस्तार

27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का कई टीवी चैनलों और यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया। 7,18,110 छात्र, 42,337 कर्मचारी और 88,544 अभिभावक ने सीधा प्रसारण देखा।

2024 राष्ट्रव्यापी भागीदारी

29 जनवरी, 2024 को सातवां संस्करण भारत मंडपम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के लिए **MyGov** पोर्टल पर 2.26 करोड़ पंजीकरण किए गए। पहली बार, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 100 छात्र शामिल हुए। इस परीक्षा पे चर्चा में छात्र, शिक्षक, अभिभावक और कला उत्सव के विजेताओं सहित लगभग 3,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

> फेल होने से जिंदगी अटक नहीं जाती है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि अपने जीवन की विफलताओं को अपना टीचर बना लें। जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं है, जीवन समग्रता में देखना चाहिए।
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

समय के सदुपयोग को लेकर रहते हैं सतर्क

छात्रों को टाइम मैनेजमेंट का गुर बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने समय के विषय में सोचना चाहिए। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे कर सकता हूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूं। मैं समय बर्बाद नहीं होने देता हूं। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम को कागज पर लिखकर तय करना और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया कि कल तीन काम तो पक्का करूंगा। तीन काम हो सकेंगे तो करूंगा और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं किए।

किताब बनाम जीवन की सफलता

कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने पूछा कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो मन में हमेशा यह चिंता होती है कि अगर मैं फेल हो गई तो। फेल होने के बाद के जो परिणाम होंगे उसके बारे में हमेशा बहुत चिंता रहती है। ऐसे में फेलियर से कैसे बच जाए? जवाब में पीएम मोदी ने सवाल किया कि स्कूल में दसवीं में, 12वीं में, 40 फीसदी, 30 फीसदी बच्चे फेल होते हैं, उनका क्या होता है? जिस पर विद्यार्थी ने कहा कि फिर से ट्राई करते हैं। पीएम मोदी ने फिर सवाल किया उसके बाद भी फेल हुए तो? इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद देते हुए कहा कि देखिए जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय यह होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं है, उसको अपना टीचर बना लें। दूसरा जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं हैं, जीवन समग्रता में देखना चाहिए।

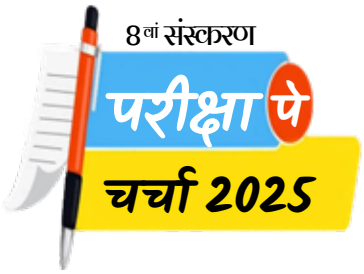

बीमारी न होने का मतलब यह नहीं है कि हम स्वस्थ हैं

पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि बीमार न होने का मतलब यह नहीं है कि हम स्वस्थ हैं। वैलनेस के तराजू पर तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है या ज्यादा नींद आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है। इस पर एक छात्र ने कहा कि सर, परीक्षा के दौरान तैयारी के समय ज्यादा नींद आती है और बाद में बिल्कुल नहीं आती है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पोषण और फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। साथ ही पीएम मोदी ने छात्रों से मौसमी फल का सेवन करने को भी कहा।

लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना जरूरी

पीएम मोदी ने कहा कि लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल-बगल के लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं क्या। आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वह स्वीकार कर रहे हैं। अब स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है।

पीएम मोदी ने छात्रों से करवाया मेडिटेशन

पीएम मोदी ने छात्रों से ध्यान यानी मेडिटेशन करवाया। उन्होंने छात्रों से कहा कि देखिए अब यह फाउंटेन चल रहा है, पल भर के लिए उसकी आवाज सुनिये, कोई गीत आपको उसमें सुनाई देता है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको भी ऑब्जर्व करो। क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? पांच आवाज एक साथ आई होंगी। आपने कभी आईडेंटिफाई किया कि कौन सी आवाज कहां से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर यह किया, आपका ध्यान केंद्रित हुआ। उसकी जो एक ताकत थी, उसके साथ अपने आप को अटैच किया। साथ ही पीएम मोदी ने प्राणायाम के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि, हां प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं।

जब शिक्षकों से कहा, बच्चों को चाहिए खुला आसमान

पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा में मैं हमेशा छात्रों के परिवार और शिक्षकों से कहता हूं कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए। उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वह अपने पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप परिवार और टीचर्स को भी मना सकते हैं।

परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए रिकार्ड छात्रों ने कराया पंजीकरण

परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) कार्यक्रम के 8वें संस्करण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। इसके लिए 3.56 करोड़ पंजीकरण हुए जबकि 1.55 करोड़ राष्ट्रव्यापी 'जन आंदोलन' गतिविधियों में शामिल हुए। इस तरह 5 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ परीक्षा पे चर्चा एक ऐतिहासिक सफर बन गया। गत वर्ष 7वें संस्करण में 2.26 करोड़ पंजीकरण हुए थे।

छात्रों के बीच तुलना न करें शिक्षक

शिक्षकों से प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से तुलना नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टीचर्स स्कूल में एक वातावरण बना देते हैं। जो चार अच्छे बच्चे होशियार होते हैं, हर बार उनको पुचकारते हैं। बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पर बैठो, तेरा काम नहीं है। यह उसको डिप्रेस्ड कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी-विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए। आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना बंद कीजिए, कुछ कहना है तो उसको अलग से बोले, देखो बेटे तुम बहुत अच्छे हो। बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दो। ऐसे में विद्यार्थी फिर सोचेगा मैं मेहनत करूं, अच्छे से अच्छा लाऊं। पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा।

संतान को समझने का कीजिए प्रयास

मां-बाप, परिवारजनों से पीएम मोदी ने आग्रह किया कि आप अपनी संतानों को समझने का प्रयास कीजिए। उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है, उसके अनुरूप वो क्या करते हैं, उसको मॉनिटर कीजिए। हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए खेलकूद में उसकी रुचि आपको दिख रही है तो उसको कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, देखेगा मोटिवेट होगा।

8वां संस्करण

परीक्षा पे चर्चा 2025

परीक्षा पे चर्चा में हुए सात ज्ञानवर्धक एपिसोड

परीक्षा पे चर्चा 2025 में सात ज्ञानवर्धक एपिसोड आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां एक साथ आईं।

- **खेल और अनुशासन** : इस विषय पर एमसी मैरीकॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज ने अनुशासन के जरिए लक्ष्य निर्धारण, संघर्ष क्षमता और तनाव प्रबंधन पर चर्चा की।
- **मानसिक स्वास्थ्य** : मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भावनात्मक मुद्दे और मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर बातचीत की।
- **पोषण** : विशेषज्ञ शोनाली सभरवाल, रुजुता दिवेकर और रेवंत हिमात्सिंगका ने खानपान की आदतें, नींद और पोषण पर छात्रों को प्रेरित किया।
- **टेक्नोलॉजी एवं वित्त** : ज्ञान अर्जित करने और वित्तीय साक्षरता के रूप में टेक्नोलॉजी को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने के विषय पर गौरव चौधरी और राधिका गुप्ता ने छात्रों से बातचीत की।
- **रचनात्मकता और सकारात्मकता** : नाकारात्मकता से दूर रहने और सकारात्मक बने रहने के लिए छात्रों को विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर ने प्रेरित किया।
- **एकाग्रता और मानसिक शांति** : मानसिक शांति और एकाग्रता के विषय पर सद्गुरु ने मंत्र दिया।
- **सफलता की कहानियां** : यूपीएससी, आईआईटी-जेईई, सीबीएसई, एनडीए, आईसीएसई के टॉपर्स और प्रतिभागियों ने परीक्षा पे चर्चा से उन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी दी।

छात्रों के साथ पीएम मोदी ने लगाए पौधे

छात्रों के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ पौधे भी लगाए। साथ ही उन्होंने पौधों की सिंचाई का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि जो पेड़ लगाए हैं उसके बगल में एक मिट्टी का मटका लगा देना चाहिए। उसमें महीने में एक बार पानी भर देना चाहिए जिससे इसका ग्रोथ जल्दी होगा।

...तो लेता स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं होते, मंत्री होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करते? तो मैंने जवाब दिया था, मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लेता।

जब एक विद्यार्थी ने सुनाई कविता

इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तू अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने, फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में, सवालों भरे तेरे मन में एक स्याही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में! ■

नारी शक्ति

नए भारत की पथ प्रदर्शक

वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होगी और उसमें लगभग 75 करोड़ आबादी महिला शक्ति की होगी। अगर उन्हें समुचित अवसर मिले तो भारत दोगुनी गति से आगे बढ़ सकता है। इसी दृष्टिकोण के साथ आधी आबादी के सामर्थ्य की पहचान कर बीते एक दशक से सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक रूप से सशक्त करने की पहल हुई है। इसी का परिणाम है कि भारत की महिलाएं आज स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, दृढ़ संकल्प से लैस हैं, उनमें सुरक्षा का भाव है... वे केवल सपने नहीं देख रहीं, बल्कि उसे साकार भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों के कारण दशकों से चली आ रही लड़की या महिला को कमतर मानने की सोच में आया है क्रांतिकारी बदलाव...

आइए जानते हैं कि जब दुनिया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) मना रही है तो आजादी के स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत में कैसे महिला शक्ति पथ प्रदर्शक के रूप में नवनिर्माण की वाहक बन रही हैं।

हमारे वेदों ने महिलाओं का आह्वान 'पुरन्धिः योषा' से किया गया है। यानी, महिलाएं अपने नगर, अपने समाज की जिम्मेदारी संभालने में समर्थ हों, महिलाएं देश को नेतृत्व दें। नारी, नीति, निष्ठा और निर्णय शक्ति के साथ नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। इसीलिए हमारे वेदों ने, हमारी परंपरा ने ये आह्वान किया है कि नारी सक्षम हों, समर्थ हों और राष्ट्र को दिशा दें। अपने इसी दृष्टिकोण के साथ भारत ने जी-20 की अध्यक्षता करते हुए नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास को वैश्विक एजेंडा बनाया और यही आज के भारत का मूलमंत्र बन गया है। इसी सोच से बीते एक दशक के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज सेना हो या स्टार्टअप, खेल जगत हो या शोध, नए भारत में बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना हो या ऐतिहासिक रूप से लिंगानुपात में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या का बढ़ना, यह बदलाव इस बात का संकेत है कि अमृत काल का नया भारत कितना सामर्थ्यशाली होगा। आज भारत पुरातन सोच से बाहर निकलकर नारी के नेतृत्व में विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है।

दरअसल, स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत ने एक तरह से विकास की बागडोर आधी आबादी को सौंप दी है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है और यह सुनिश्चित किया है कि उनकी कार्यक्षमता में विस्तार हो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के समान महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी से भारत की जीडीपी में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि 50 प्रतिशत कुशल महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं तो विकास दर 1.5 प्रतिशत बढ़कर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष हो सकती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की गई हैं, उनके केंद्र में महिलाओं का जीवन आसान बनाना और महिलाओं को रोजगार-स्वरोजगार

के नए अवसर देने के साथ महिला सशक्तीकरण रहा है। महिला उत्थान में जहां पुरानी धारणा और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की सफलता जो आज दिख रही है, सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई है, उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनसे मां और बच्चे, दोनों के जीवन को बचाने में सफलता मिली है। आयुष्मान भारत योजना की भी लगभग 50 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं ही हैं। केंद्र सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण हो या फिर सैनिटेरी पैड्स से जुड़ी योजना, इससे बेटियों के ड्रॉप आउट रेट में बहुत कमी आई है। स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है, इससे एक सुरक्षित माहौल भी उन्हें मिला है। सुकन्या समृद्धि योजना से देशभर की करोड़ों बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए पहली बार बचत खाते खुले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बेटियों की शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

केंद्र सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी काम और किसी भी कार्यक्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश न हो। इसलिए माइनिंग से लेकर सेना में अग्रिम मोर्चों तक, हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को खोल दिया गया है। सैनिक स्कूलों से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों तक में अब बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही हैं। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। इतना ही नहीं, आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भी योजनाएं लागू की गई हैं।

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा

स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को दिया नया आधार

90.87
लाख स्वयं सहायता समूह

10.05
करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब तक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है।

- 9.74 लाख करोड़ रुपये मिशन की शुरुआत से 15 दिसंबर, 2024 तक स्वयं सहायता समूहों को दिए जा चुके हैं।
- 25,385 महिला कल्याण सहकारी समिति पंजीकृत हैं। वहीं 1,44,396 डेयरी सहकारी समिति है, जहां काफी संख्या में ग्रामीण महिलाएं कार्यरत हैं।

03
करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने।

1.25
करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं जनवरी, 2025 तक।

लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सरकार पांच लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन देती है।

गांव में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का आधार ड्रोन दीदी

1,094
ड्रोन वित्त वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूह की ड्रोन दीदियों को वितरित किए गए हैं, जिनमें 500 ड्रोन नमो दीदी योजना में वितरित किए गए हैं।

- गांव में इन दिनों ड्रोन दीदी की खूब चर्चा हो रही है। महिलाओं को ड्रोन चलाते देखकर एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांव में आया है।
- इस योजना में 2025-26 तक 15 हजार ड्रोन दिए जाने हैं। साथ ही, महिलाओं को कृषि कार्यों व ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाना है ताकि आजीविका के नए अवसर पैदा हों।

आर्थिक सशक्तता
नारी सशक्तीकरण का नया आधार

नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प के केंद्र में है तो उनकी आर्थिक मजबूती नए भारत का आधार। सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय नारी शक्ति की 'आर्थिक खुशहाली' को ध्यान में रखकर न सिर्फ योजना और कार्यक्रम बना रहे हैं बल्कि माइक्रो लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है...

जहां स्टैंडअप इंडिया और मुद्रा योजना महिलाओं के लिए बैंक लोन और उद्यमशीलता कार्यकलापों को सुगम बनाती है तो वहीं स्टार्टअप इंडिया समेत कई तरह के फंड में नारी शक्ति के लिए आरक्षित फंड और मेंटर उनकी राह भी आसान करते हैं। पीएम - स्वनिधि, मनरेगा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड जैसी योजनाएं रोजगार-स्वरोजगार और लोन की सुविधाएं महिलाओं को प्रदान करती हैं जिनकी ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं।

30,000

करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई कोविड के दौरान अप्रैल से जून, 2020 के बीच 20 करोड़ महिलाओं के खाते में।

जनधन योजना: तैयार हुई आर्थिक स्वतंत्रता की नींव

दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल में महिलाएं सबसे बड़ी लाभार्थी।

30.37

करोड़ यानी करीब 56 फीसदी खाते प्रधानमंत्री जनधन पहल के तहत महिलाओं के खुले 15 जनवरी, 2025 तक, कुल जनधन खातों की संख्या 54.58 करोड़ पहुंची।

महिला सम्मान बचत पत्र यानी बचत को अधिक ब्याज की मजबूती

- 43 लाख से अधिक खाते योजना में 31 अक्टूबर, 2024 तक खोले जा चुके हैं। महिला और नाबालिग लड़कियों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना 'आजादी का अमृत महोत्सव' के यादगार के रूप में 31 मार्च, 2023 को शुरू की गई थी।
- इसमें कोई भी महिला स्वयं या नाबालिग लड़की के नाम से अभिभावक 31 मार्च, 2025 तक या उससे पहले खाता खोल सकते हैं।
- योजना में खाताधारक न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख के साथ दो वर्ष की अवधि के लिए खाता खोल सकते हैं। इस खाते में ब्याज दर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

24 फीसदी से ज्यादा कम हुई वयस्क महिलाओं में गरीबी दर

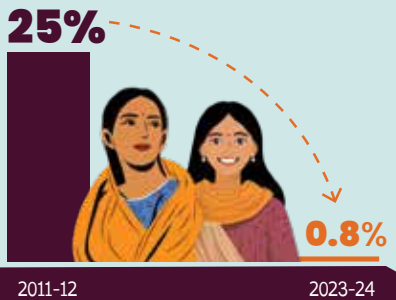

बढ़ते बीमा क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी बीमा सखी

- महिलाओं को तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास का भागीदारी बनाने के लिए उन्हें वित्तीय मजबूती दी जा रही है। इसी कड़ी में 9 दिसंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की।
- 1,00,076 महिलाओं ने बीमा सखी बनने के लिए कराया है पंजीकरण, 51,552 ने बीमा सखी के रूप में काम शुरू किया। करीब 49 हजार का अभी चल रहा है प्रशिक्षण।
- 77,000 से अधिक पॉलिसी इन बीमा सखियों ने प्राप्त की। 85 करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम आया।

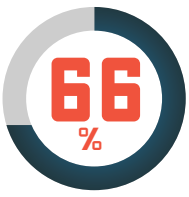

कारोबार बीमा सखियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया। अब तक कराए गए कुल बीमा संख्या में 62 फीसदी महिलाओं ने पॉलिसी ली हैं।

आवरण कथा

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस विशेष

स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना: आसान हुई राह तो स्टार्टअप इंडिया ने दी नई दिशा

स्टैंडअप इंडिया

उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने वाली स्टैंडअप इंडिया की 83 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं। योजना में हर बैंक को कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच लोन देने का लक्ष्य दिया गया है।

2,15,582
कुल महिला लाभार्थी

2,59,797
कुल स्वीकृत लोन संख्या

मुद्रा योजना

मुद्रा योजना में स्वरोजगार के लिए चार श्रेणी में 50 हजार रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है ताकि वह अपने व्यावसायिक कार्यकलापों को स्थापित व विस्तारित कर सकें।

70%
लाभार्थी महिलाएं हैं

34.96
करोड़ महिला लाभार्थी

51.67
करोड़ कुल स्वीकृत लोन संख्या

इनोवेशन और रिसर्च

- विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसर को बढ़ावा देने वाली पावर योजना 2020 में शुरू की गई। अनुसंधान अनुदान में 97 परियोजनाओं को पोषित किया गया जिसमें 42 फेलोशिप महिलाओं को दी गई।

नारी के नेतृत्व में विकास की राह मजबूत करता जेंडर बजट, 5 वर्ष में करीब 3 गुना बढ़ा

2025-26	4.49
2024-25	3.27
2023-24	2.38
2022-23	1.71
2021-22	1.53

(नोटः आंकड़े लाख करोड़ रुपये में)

सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक सशक्तीकरण

नए भारत की सोच में महिला सशक्तीकरण अब केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति का सम्मान नए भारत को दर्शाता है। पद्म पुरस्कारों में समाज के लिए प्रेरणा बनीं गुमनाम महिलाओं को सम्मानित करना, अमृत यात्रा की सुखद अनुभूति कराता है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुईं करीब 10 करोड़ महिलाएं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, वंचित परिवारों से हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा है, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा है और केंद्र सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपये तक बढ़ा दी है, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके। उनकी कार्य क्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। आज देश के अनेक गांवों में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है, इससे एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांव में आया है, महिला के हाथ में ड्रोन चलाते हुए देख कर गांव के लोगों का महिला के प्रति देखने का नजरिया बदल रहा है और आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम करके लाखों रुपये कमाने लगी हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हमेशा से बहुत बड़ा स्थान रहा है। केंद्र सरकार इस भूमिका का और विस्तार कर रही है। आज गांव में बैंक सखी और बीमा सखी के रूप में महिलाएं ग्रामीण जीवन को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं। गांव-गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए नई क्रांति कर रही हैं। गांवों की 1 करोड़ 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के लिए उसके सशक्तीकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। करोड़ों महिलाओं ने पहली बार मुद्रा

हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रत्येक विकास पहल में हम बालिकाओं को सशक्त बनाने और अपनी नारी शक्ति को मजबूत करने को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। हमारा ध्यान बालिकाओं के लिए सम्मान के साथ-साथ अवसर सुनिश्चित करने पर है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

योजना में लोन लेकर उद्योग क्षेत्र में कदम रखा है और उद्योगपति की भूमिका में आई हैं। महिला और नाबालिग लड़कियों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना आजादी के अमृत महोत्सव के यादगार के रूप में 31 मार्च 2023 को शुरू की गई थी। 31 अक्टूबर, 2024 तक इसके अंतर्गत 43,30,121 खाते खोले जा चुके हैं। इस महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के अंतर्गत खाता किसी महिला द्वारा स्वयं के लिए या किसी नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा 31 मार्च, 2025 तक या उससे पहले खोला जा सकता है।

वैश्विक एजेंडा बना नारी के नेतृत्व में विकास

वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तीकरण की दिशा में ध्यान केंद्रित किया है। इसी कड़ी में नए भारत की नई संसद में 20-21 सितंबर, 2023 नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक बना। कभी राजनीति और सत्ता को सर्वोपरि मानकर संसद व विधायिका में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल को दशकों तक लटकाया गया या यूं कहें कि केवल बातें हुईं, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यथार्थ बना दिया। इसके

महिलाओं की आर्थिक दमदारी की कहानी कहते आंकड़े

2.21

करोड़ के लगभग महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई हैं पंजीकृत।

1.63

लाख से ज्यादा महिला नेतृत्व वाली एमएसएमई रजिस्टर हैं जेम पोर्टल पर, 31 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का मिला ऑर्डर।

2.26

करोड़ से अधिक महिला किसान को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त तक राशि जारी की गई।

10%

की छूट वार्षिक गारंटी शुल्क में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को समर्थन के लिए दी जाती है।

- 90% दी जाती है गारंटी कवरेज महिलाओं को जबकि अन्य उद्यमियों को 75% गारंटी कवरेज दी जाती है।
- 100 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी या 300 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है।
- 32 हजार से अधिक महिलाओं को दिसंबर, 2024 तक पीएम जनमन योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया, कुल प्रशिक्षण 38,396 को दिया गया।
- 44.62 लाख पीएम स्वनिधि लोन महिलाओं को स्वीकृत। यह कुल स्वीकृत 99.15 लाख लोन का 45% है।
- 75.46% है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कुल नामांकन में महिला कारीगरों का नामांकन। 1.04 लाख महिला लोन खाते हैं पीएम विश्वकर्मा लोन योजना में।
- 10 करोड़ महिलाओं का बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किया गया।
- 22.84 करोड़ महिलाओं का बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में किया गया।
- 41.7% हो गया 15 वर्ष व अधिक के लिए रोजगार अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 में, जो 2017-18 में महज 23.3% था।
- 1.50 करोड़ महिलाएं ईपीएफओ में शामिल हुए।
- 39% लाभार्थी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में महिलाएं हैं। यह क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
- 33% महिलाओं को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में शामिल करने की अनिवार्यता है। यह 15-35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है।
- 3.16 लाख से अधिक महिला ने वस्त्र मंत्रालय की कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण की समर्थ योजना में 7 फरवरी, 2025 तक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया।

सुरक्षित महिला समृद्ध राष्ट्र

किसी देश में महिलाओं की सुरक्षा कई कारकों का परिणाम होती है। इनमें सख्त कानूनों के माध्यम से कड़ाई से अपराधों की रोकथाम, न्याय की प्रभावी डिलीवरी, समय पर शिकायतों का निवारण और पीड़िताओं के लिए आसानी से सुलभ सहायता शामिल है। केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में इस दिशा में उठाए हैं कई अहम कदम...

भारत के तीन नए कानून में जिस तरह के नए प्रावधान किए गए और सख्ती बढ़ाई गई है उससे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कमी आ रही है। भारत की प्रगति नारी शक्ति से प्रेरित है। अगर महिलाओं को अवसर दिए जाएं और वे नीति-निर्माण का हिस्सा बनें तो इससे देश की प्रगति में और गति आ सकती है।

758
जिलों में 802 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं। 31 दिसंबर, 2024 तक 10.43 लाख महिलाओं को इसमें सहायता मिली है।

सख्त कानूनी प्रावधानों के साथ जांच, मजबूत तंत्र की दिशा में कदम

- महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने की दिशा में पहल। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को पारित कर 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार के दोषियों के लिए फांसी सहित कड़ी सजा का प्रावधान।
- यौन अपराध के मामलों में पुलिस जांच 2 माह में और ट्रायल अगले दो माह में पूरा करने का प्रावधान। आदतन यौन अपराधियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस।
- महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 14 राज्यों ने साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैबोरेटरी शुरू की है।
- निर्भया कोष द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में से 8 शहरों (अहमदाबाद, बंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके तहत सचेत करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, सीसीटीवी, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है।

सुरक्षा और बचाव की दिशा में मिशन शक्ति की पहल

- महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण और कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और सूक्ष्म ऋण तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं पर लैंगिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और देखभाल की जिम्मेदारी का समाधान करना है।
- वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) के माध्यम से एक ही जगह प्रदान की जाने वाली एकीकृत सेवाएं जैसे पुलिस, चिकित्सा और कानूनी सहायता, परामर्श और मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहायता, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करती हैं।
- एक टोल-फ्री महिला हेल्पलाइन (181) आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता भी प्रदान करती है। इस पर 2.04 करोड़ कॉल आईं, 83.60 लाख से अधिक महिला को सहायता मिली।

लिए उन्होंने अवसर भी विशेष बना दिया और संसद के नए भवन में प्रवेश के लिए विशेष प्रयोजन के साथ विशेष सत्र बुलाया। अब जब भी नए संसद भवन की पहली शुरुआत की बात होगी, हर भारतवासी और विशेष रूप से नारी शक्ति का माथा गौरव से ऊंचा होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है। यह नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। यह अमृतकाल में 'सबका प्रयास' से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा और बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारना,

भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। नए सदन का पहला निर्णय-नारी शक्ति वंदन अधिनियम से मातृ शक्ति के आशीर्वाद से नए सदन का आरंभ हुआ।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पैनिक बटन जैसी पहल से अब आसान हुआ सफर

- टैक्सी में जीपीएस और पैनिक बटन जैसी व्यवस्था पहली बार महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई।
- 'मेरी सहेली' पहल के तहत लंबी दूरी की ट्रेनों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की पूरी यात्रा यानी यात्रा की शुरुआत वाले स्टेशन से लेकर गंतव्य स्टेशन तक की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

सेरोगेसी से लेकर गर्भपात तक नियमन

- आर्थिक तंगी के चलते अविवाहित महिलाओं की कोख को किराए पर देने के मामलों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में सरोगेट मां के हितों की रक्षा के लिए सरोगेसी कानून लागू किया है। इसमें शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से जुड़े प्रावधान किए गए हैं।
- हिंसा पीड़ित महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को मंजूरी दी। इसके तहत गर्भपात की समय सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते किया गया।

शी बॉक्स

शी-बॉक्स पोर्टल **https://shebox.wcd.gov.in** एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013' के विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

- शिकायतकर्ता का विवरण गोपनीय होता है।

90 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होती है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट

747
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय 406 **POCSO** न्यायालय सहित कार्यरत, दिसंबर 2024 तक

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को लागू करने और विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) से जुड़े मामले निपटारे के लिए सरकार ने अक्टूबर 2019 में एक केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की। इस योजना का उद्देश्य बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष पीओसीएसओ अदालतों सहित फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना करना है।

पेटेंट फाइलिंग में 345 गुना बढ़ी महिलाओं की संख्या

उज्ज्वला से धुआं मुक्त हुई रसोई

महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना परिवर्तनकारी कदम साबित हुई है।

10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत।

लाभ... विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि पारंपरिक ईंधन-लकड़ी, कोयला आदि से खाना पकाने से भारत में सालाना 5 लाख मौतें होती थी लेकिन केंद्र सरकार के इस प्रयास से महिलाओं में सांस संबंधी बीमारी के मामलों में 20 फीसदी की कमी आई है।

बेटियों को आत्मरक्षा के गुर

समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने की शुरुआत की गई।

क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना, नारी के नेतृत्व में विकास का नया युग देश में लाने की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लगभग तीन दशक से इस बिल को पारित कराने के लिए प्रयास हो रहा था। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह-तरह की बाधाएं थीं, दशकों पुराने अड़ंगे थे लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है तो परेशानियों को पार किया जाता है। यह भी अपने आपमें एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला।

सामाजिक बदलाव की नई कहानी के केंद्र में नारी

देश की आधी आबादी के विकास के बिना देश को विकसित बनाना मुश्किल है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने इस बात को मजबूती से समझा है। बात चाहे स्वास्थ्य की हो या फिर सामाजिक उत्थान की, बदलाव की हर नई कहानी के केंद्र में अब नारी शक्ति है। यही वजह है कि पिछले एक दशक से आधी आबादी के नेतृत्व में विकास को महत्व दिया जा रहा है। सरकार की इस नीति का ही असर है कि देश की आधी आबादी कठिनाई और चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भरता, शिक्षा और समानता की ओर तेजी से बढ़ रही है...

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था और प्रसव के कारण मजदूरी के नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजा प्रदान करती है। यह योजना पहले प्रथम बच्चे तक सीमित थी लेकिन अगर बच्चा लड़की है तो इसे बढ़ाकर दूसरे बच्चे को भी कवर किया गया है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।

5,000 रुपये का मातृत्व लाभ पहले बच्चे के लिए सीधे लाभार्थी के खाते में दिया जा रहा है इस योजना के तहत।

16,418.12 करोड़ रुपये दिए गए 3.69 करोड़ लाभार्थियों को दिसंबर 2024 तक।

पात्र लाभार्थियों के दूसरे बच्चे को भी पीएमएमवीवाई के तहत 6,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो।

बेटियों के जन्म से ही रखा जा रहा विशेष ख्याल

संस्थागत प्रसव
97.3% 2023-24
61% 2014-15

मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट

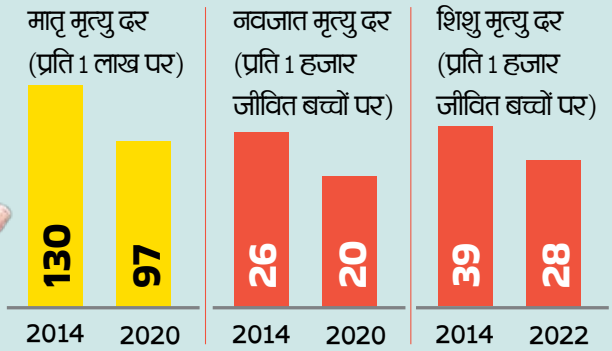

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति हजार 2014 में 45 से घटकर 2020 में 32 हो गई।

जन्म के समय लिंग अनुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 930 हुआ।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करेगा। वर्ष 2047 तक के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होगा। महिला सशक्तीकरण में यह महिला नेतृत्व को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा, संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा। यह 140 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत भागीदारी रखने वाली मातृ शक्ति का सच्चे अर्थ में सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी के नेतृत्व में विकास की बात समग्र विश्व के सामने रखी। जी-20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने दुनिया को यह अहसास

10 वर्ष या उससे अधिक उम्र की शिक्षा प्राप्त लड़कियों की संख्या में

15%

से अधिक की वृद्धि हुई है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लागू होने के बाद।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत बच्ची और महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मजबूती के लिए कई अहम पहल की गई हैं।

4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत।

2.64

लाख करोड़ रुपये सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कराए गए।

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

मातृत्व लाभ अधिनियम

- इसके अनुसार 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच की सुविधा शुरू की गई।
- सरकार ने सवैतनिक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया, जिसमें आठ सप्ताह से अधिक प्रसव की तारीख से पहले नहीं होगा।
- महिला कर्मी को सौंपे गए काम की प्रकृति के आधार पर नियोक्ता और महिला की सहमति के साथ घर से भी काम करने का प्रावधान किया गया।

मिशन पोषण 2.0

देशभर में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मिशन पोषण की शुरुआत की गई।

अपेक्षित सफलता के बाद मार्च, 2018 को मिशन पोषण का दूसरा चरण लागू किया गया।

2024 तक
10,02,05,340
लाभार्थी
ले चुके हैं लाभ

कराया कि मातृ शक्ति, बेटियां न केवल नीतियों में सहभागिता कर सकती हैं, बल्कि नीति-निर्धारण में अपने पद को भी सुरक्षित कर पाने में सक्षम हैं। इसकी वजह है कि वर्तमान केंद्र सरकार के लिए महिला सशक्तीकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक संकल्प है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वेतन के रूप में मिली सारी राशि को गुजरात सचिवालय के कर्मचारियों के बच्चियों की पढाई के लिए दान दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें जितनी भेंट मिली थी उसकी नीलामी से मिलने वाली राशि भी बच्चियों की पढ़ाई के लिए दान दी थी।

कल्पना कीजिए कि आप 140 करोड़ देशवासियों के चुने नेता हैं, जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा प्रशंसक समूह है और आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से 7 महिलाओं को पूरे दिन के लिए सौंप देते हैं। कैसी अनुभूति होगी आपको। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना ट्विटर (अब एक्स) अकाउंट 7 महिलाओं को सौंप दिया था। कथनी और करनी में साम्यता का यह अद्भुत उदाहरण ही दरअसल नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति को समान अधिकार और अवसर दे रहा है, जहां महिलाएं भी सुरक्षा और सम्मान के साथ सशक्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।

इतना ही नहीं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2014 के बाद से तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। भारत में लगभग एक-चौथाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक महिलाएं हैं। चंद्रयान, गगनयान और मिशन मंगल जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता के पीछे महिला वैज्ञानिकों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का हाथ है। आज भारत में उच्च शिक्षा में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक संख्या में प्रवेश ले रही हैं। भारतीय वायुसेना में महिला पायलट अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। सभी सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को ऑपरेशनल भूमिकाओं और लड़ाकू मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है। देश के अंदर बालिकाओं का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए शुरू हुई सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले महिला पायलटों की संख्या 5 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह संख्या 15 प्रतिशत है, जो पिछले 10 साल में बढ़ी है। सामाजिक स्तर पर भी तीन तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, कानून बनाकर उन्हें रोका है। करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को आज तीन तलाक की अमानवीय कुप्रथा से सुरक्षा मिली है। इस कानून के लागू

उच्च शिक्षा में बेटियां

उच्च शिक्षा में महिलाओं का दाखिला वर्ष 2015 में 1.57 करोड़ था, जो 31.6% बढ़कर वर्ष 2022 में 2.07 करोड़ हो गया।

28% से ज्यादा की बढ़ोतरी पिछले 10 वर्ष में उच्च शिक्षा में नामांकन में हुई है।

- **STEM** (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथेमैटिक्स) पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन बालिकाओं व महिलाओं का हुआ है, यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है।
- माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सकल नामांकन अनुपात (**GER**) 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 2023-24 में 78% हो गया है।

एक रुपये में सेनेटरी नैपकिन

देशभर में 10 हजार से ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपये में सैनेटरी पैड बेचने की शुरुआत की गई। सरकार ने सेनेटरी पैड को किफायती और आसानी से सुलभ बनाने के लिए 100% कर मुक्त कर दिया है।

60 करोड़ से अधिक सेनेटरी पैड बेचे गए हैं अब तक।

तीन तलाक के खिलाफ कानून

केंद्र सरकार ने एक अगस्त 2019 को तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया। तीन तलाक को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया।

जल जीवन मिशन से मिली पानी के झंझट से मुक्ति

ग्रामीण भारत में एक समय पीने के पानी के लिए दूर तक बर्तन लेकर जाने की तस्वीरें दिखाई देती थीं। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत की इस तस्वीर को अब बीते समय की याद बना दिया है।

15.44 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच गया है नल से जल।

17% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन थे अगस्त, 2019 तक जो आंकड़ा अब बढ़कर 79.74% पहुंच गया है।

स्वच्छ भारत मिशन से बढ़ा सम्मान

2014 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। महिलाओं के आत्मसम्मान के नजरिए से यह अहम कदम साबित हुआ। स्वच्छ विद्यालय मिशन के तहत, यह सुनिश्चित किया गया कि सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए कम से कम एक शौचालय हो।

12
करोड़ से अधिक घरों में बनाए जा चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय।

3,00,000
मौतें होने से बचाई जा सकी हैं स्वच्छ भारत मिशन की वजह से।

पीएम आवास योजना से मिला घर का हक

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर घर देने को प्राथमिकता दी गई। वहीं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के दूसरे चरण के तहत महिला मुखिया के नाम पर घर देने की अनिवार्यता तय।

4.53
करोड़ मकान को मंजूरी, 2 फरवरी, 2025 तक।

3.56
करोड़ मकान का निर्माण हो चुका है पूरा।

75%
स्वीकृत मकान का स्वामित्व पूरी तरह या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है।

महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में विश्व में अव्वल

महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सरकार ने संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किए। महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। भारत वर्तमान में विश्व के उन 15 देशों में से एक है, जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। भारत में स्थानीय सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है।

- 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (संविधान 106वां संशोधन) के अनुसार लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
- 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम 33% स्थान आरक्षित किए हैं।
- पंचायती राज संस्थान में अभी 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है।

होने से कुछ ही वर्षों में तीन तलाक के मामले में 80-82 प्रतिशत की कमी आई है।

मातृ शक्ति की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था- "महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है।" निःसंदेह महिलाएं समाज में एक अभिन्न भूमिका निभाती हैं। उनकी प्रगति के बिना समाज की समग्र प्रगति रुक जाती है। महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि सामाजिक विकास के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। इसे स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने देश के भीतर नारी शक्ति यानी महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता के साथ सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं भारत की समृद्धि की यात्रा में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "देश को आगे ले जाने की क्षमताओं में महिला के नेतृत्व वाला विकास अहम है।" भारत सरकार महिला नेतृत्व वाले विकास को राष्ट्र की प्रगति का केंद्रीय आयाम और भारत को मजबूत करने की आवश्यकता मानती है। बीते एक दशक में भारत सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है।

केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए जिन चार जातियों पर ध्यान केंद्रित किया है, उनमें गरीब, युवा, अन्नदाता किसान के साथ-साथ महिलाएं भी शामिल हैं। उन लोगों की आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब वे उन्नति करते हैं तो देश की प्रगति होती है। इन चारों जातियों को अपना जीवनस्तर बेहतर बनाने

आवरण कथा
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस विशेष

महिला की भागीदारी

पुलिस से सेना तक, सैनिक स्कूलों में खुला प्रवेश

बेटियों को हर क्षेत्र में समान अवसर मिले इसलिए ऐसे रास्ते खोले जो दशकों से बेटियों के लिए बंद थे। सेना में फाइटर प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी हो या फिर सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश।

महिला पायलट

15%

से अधिक है भारत में महिला पायलट की संख्या। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वीमन एयरलाइन पायलट्स के अनुसार विश्व में यह संख्या महज पांच फीसदी है।

भारतीय सेना के सैन्य पुलिस कोर में अन्य रैंक पर महिलाओं की भर्ती का 2019 में किया प्रावधान

2.63

लाख से अधिक महिलाएं देशभर में पुलिस सेवा में तैनात हैं। 2013-14 के मुकाबले यह संख्या तीन गुना है।

10,493

सेना में सेवारत महिला अधिकारियों की संख्या हैं। जिसमें 4,734 नर्सिंग सेवा अधिकारी हैं। 2014-15 में कुल संख्या तीन हजार थी।

शक्ति सदन

2,92,681

महिलाओं को अब तक मदद दी जा चुकी है

404 **शक्ति सदन के जरिए।**

शक्ति सदन, तस्करी की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है।

- एक जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम का उद्घाटन किया गया।
- सभी सैनिक स्कूलों में 2021-22 सत्र से कक्षा 6 में रिक्तियों के 10 फीसदी सीट पर लड़कियों का प्रवेश शुरू कर दिया है।
- एनडीए 2022 के लिए नवंबर 2021 में लड़कियों का प्रवेश शुरू कर दिया गया। वायु सेना में 20 महिला लड़ाकू पायलट को कमीशंड किया है।
- नौसेना में 28 महिला अधिकारियों को पोतों पर तैनात किया गया है।

पद्म सम्मान

258

महिला को पिछले 11 वर्ष में दिए गए हैं। इस वर्ष भी 23 महिला को मिला सम्मान।

के प्रयास में सरकार द्वारा सहायता की आवश्यकता है और उन्हें सरकार से सहायता मिल भी रही है। इन लोगों का सशक्तीकरण होने से और उनके कल्याण से देश भी आगे बढ़ेगा। नारी शक्ति को प्रोत्साहन देते हुए केंद्र सरकार ने उद्यमशीलता, जीवन में सुगमता और गरिमा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को गति दी गई है। मुद्रा योजना की लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थी महिला उद्यमी ही हैं। इसके तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण दिए गए हैं। एक अध्ययन के अनुसार, इस योजना से महिलाओं की आर्थिक शक्ति

में सुधार के साथ सामाजिक फैसलों में भागीदारी भी बढ़ी है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। STEM पाठ्यक्रमों के लिए होने वाले नामांकन में बालिकाओं और महिलाओं की भागीदारी 43 प्रतिशत हो गई है। यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है। कार्यक्षेत्र में महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए गए हैं, उसमें से करीब करीब 75 प्रतिशत मकान ऐसे हैं जिसका मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। देश में इस समय 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह भी काम कर रहे हैं, जिनमें करीब 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा लाखों करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है।

सुरक्षा के साथ सशक्तीकरण

जब महिलाएं सुरक्षित और समृद्ध होती हैं, तो दुनिया भी समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तीकरण विकास को बल देता है। शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को प्रेरित करती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनके विचार सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला-नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है। भारत ने इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वह एक साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि से आती हैं। लेकिन अब वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करती हैं और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रक्षा बल की कमांडर-इन-चीफ के रूप में योगदान दे रही हैं। लोकतंत्र की इस जननी में 'मतदान का अधिकार' भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ से ही महिलाओं सहित सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किया गया था। चुनाव लड़ने का अधिकार भी सभी को समान आधार पर दिया गया।

महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और विकास में समान रूप से सहभागी बनाने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा से जुड़े अनेकों प्रयास किए गए हैं। आज देश की प्राथमिकता, महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने और भारत की विकास यात्रा में उनकी संपूर्ण भागीदारी में है। बेटे-बेटी को एक समान मानते हुए बेटियों के विवाह की आयु को भी 21 वर्ष करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। आज देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े कानून हैं, बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में फांसी का भी प्रावधान किया गया है। देशभर में बड़ी संख्या में फास्टट्रैक कोर्ट भी बनाई जा रही हैं। कानूनों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए भी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। थानों में महिला सहायता डेस्क की संख्या बढ़ाना हो, चौबीस घंटे उपलब्ध रहने वाली हेल्पलाइन हो, साइबर क्राइम से निपटने के लिए पोर्टल हो, ऐसे अनेक प्रयास महिलाओं की सुरक्षा का कवच बन रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति से काम कर रही है। सिर्फ कानूनी संरक्षण ही नहीं, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए केंद्र सरकार ने तो अभियान चला रखा है। केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं के जरिए परिवार की महिलाओं को ही केंद्र में रखकर दस्तावेज दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, पहले जम्मू-कश्मीर में गैर कश्मीरी से विवाह करने पर महिलाओं और उसके बच्चों को पैतृक संपत्ति के हक से वंचित कर दिया जाता था लेकिन अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद इस क्षेत्र की महिलाओं को उसका हक मिला है। प्रवासी भारतीयों द्वारा शादी करने और फिर छोड़ देने जैसे मामलों में भी कानून को सख्त बनाया गया है।

मिशन शक्ति सरकार का एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण और कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना है। इस मिशन का उद्देश्य कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और सूक्ष्म ऋण तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं पर लैंगिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और देखभाल की जिम्मेदारी का समाधान करना है। वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) के माध्यम से एक ही जगह प्रदान की जाने वाली एकीकृत सेवाएं जैसे पुलिस, चिकित्सा और कानूनी सहायता, परामर्श और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करती हैं। एक टोल-फ्री महिला हेल्पलाइन (181) आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता भी प्रदान करती है। मिशन शक्ति ने महिलाओं को आगे बढ़ने और समाज में सक्रिय योगदान देने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया है।

निश्चित रूप से महिलाओं को कल्याण का लाभ लेने से सशक्तीकरण के एजेंट के रूप में परिवर्तित करके, सरकार अपने देश की महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाने में सफल रही है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्यमिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तक, इस तरह की पहलों ने महिलाओं के जीवन में जबरदस्त सुधार किए हैं तथा देश की समग्र प्रगति में योगदान दिया है। आज बात केवल महिलाओं के विकास की नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास की है।

विकसित भारत की तस्वीर
'बचत भी, विकास भी' मॉडल

बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं विकसित भारत के रोडमैप का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के इसी संकल्प की तस्वीर के साथ 10 साल के कार्यकाल के महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र कर 'बचत भी, विकास भी' का मॉडल भी सामने रखा....

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर विपक्ष की ओर से उठाए गए हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सधे हुए अंदाज में दिया। लोकसभा में करीब 95 मिनट और राज्यसभा में करीब 92 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने भारत की उपलब्धियों के बारे में, दुनिया की भारत से अपेक्षाओं के बारे में और भारत के सामान्य मानव के आत्मविश्वास, विकसित भारत का संकल्प जैसे सभी विषयों की विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने देश को आगे की दिशा भी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2025 में हैं, एक प्रकार से 21वीं सदी का 25 प्रतिशत हिस्सा बीत चुका है। समय तय करेगा 20वीं सदी के आजादी के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25 साल में क्या हुआ, कैसा हुआ? लेकिन राष्ट्रपति का संबोधन देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए नया विश्वास जगाने और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है। विकसित भारत कोई सरकारी नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। 20-25 साल के कालखंड में दुनिया के कई देशों ने विकसित बनकर दिखाया है, तो भारत के पास तो सामर्थ्य अपार है। संसद के दोनों सदनों में अपने संवाद के दौरान किन-किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा... **पढ़िए संपादित अंश...**

विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की मजबूती पर...

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है, वहां संभावनाएं भी बढ़ती है। दिल्ली-यूपी को जोड़ने वाली पहली नमो रेल, ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सभी प्रमुख शहरों तक पहुंचे, यह हमारी जरूरत और दिशा है। मेट्रो रेल का नेटवर्क भी 1,000 किलोमीटर पार कर गया है और 1,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है। विकासशील से विकसित राष्ट्र की यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी ताकत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी जरूरी है कि वो समय से पूरे हों। कांग्रेस के कालखंड में अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये उनकी राजनीति का हिस्सा था। प्रोजेक्ट पर राजनीतिक का तराजू रहता था। एक प्रगति नाम की व्यवस्था बनाई। नियमित रूप से मैं स्वयं इस प्रगति प्लेटफार्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करता हूं। करीब-करीब 19 लाख करोड़ रुपये के ऐसे जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए थे।

अटकाने, लटकाने और भटकाने की संस्कृति खत्म

- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस प्रगति पर अध्ययन की रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि प्रगति के अनुभवों से सीखते हुए अन्य विकासशील देशों के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में क्रांति लाने का एक मूल्यवान अवसर है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सही प्लानिंग और समय पर एग्जीक्यूशन, इसके लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। इसमें 1,600 डेटा लेयर्स हैं।
- यह तो अभी हमारी तीसरा ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार, आधुनिक और सक्षम भारत बनाने एवं विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं।

गरीबों के उत्थान पर...

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं, बल्कि सच्चा विकास दिया है। हमारी सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए अधिकतम अवसर पैदा करने के लिए काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब ही गरीबी को परास्त करें, उस दिशा में योजनाओं को आकार दिया है। हमें उनके सामर्थ्य पर भरोसा है। अब सारे अध्ययन बार-बार यह कह चुके हैं कि गत 10 वर्ष में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं।

झूठे वादे बनाम सच्चा विकास

- बारिश के दिनों में कच्ची छत, उसकी प्लास्टिक की चादर वाले छत उसके नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। ये हर कोई नहीं समझ सकता। अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं।
- सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण दिया। बहुत ही स्वस्थ शांत तरीके से पूरे राष्ट्र ने इस बात को स्वीकार किया।
- शिक्षा नीति में बदलाव किए हैं। मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में परीक्षा, इस पर बल दिया है। बदलाव से आज गरीब का बच्चा डॉक्टर-इंजीनियर बनने के सपने देखने लगा।

गांव, किसान और कृषि की बात...

सशक्त किसान तो सशक्त राष्ट्र की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूरल इकोनॉमी के हर क्षेत्र को स्पर्श करने का प्रयास किया हैं। पीएम ने कहा कि हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग निर्णय से एक लाख करोड़ रुपये का फर्क पड़ा है, करीब-करीब यह सारा पैसा किसानों की जेब में गया है। विकसित भारत के 4 स्तंभों में किसान एक मजबूत स्तंभ है। बीते दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है।

मील के पत्थरों का जिक्र

- किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में पहुंचे हैं।
- रिकॉर्ड एमएसपी बढ़ाई और पहले की तुलना में बीते दशक में तीन गुना अधिक खरीद की है। किसानों को आसान और सस्ता लोन मिले, उसमें भी तीन गुना वृद्धि की गई है। पीएम फसल बीमा के तहत 2 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं।
- डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की प्रेरणा से 100 से ज्यादा बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, जो दशकों से लटकी हुई थीं, उसको पूरा करने का अभियान चलाया। नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया।

महिला सशक्तीकरण और उत्थान की बात...

महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में सरकार के मजबूत इरादों का जिक्र कर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। ये महिलाएं वंचित परिवारों से हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं। सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपये तक बढ़ा दी है। लखपति दीदी योजना को जब से मैंने आगे बढ़ाया है, अब तक करीब सवा करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। ड्रोन दीदी से एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांव में आया है। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के सशक्तीकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। इसी तरह स्टैंड अप इंडिया, जिसका मकसद था एससी, एसटी समुदाय सहित किसी भी समाज की महिला, उसको बैंक से एक करोड़ रुपये का बिना गारंटी का लोन, ताकि वो अपना कार्य करे। हमने इस बार बजट में इसको डबल कर दिया है।

मजबूत इरादों का जिक्र

सामने रखे बदलाव की कहानी कहते आंकड़े

पीएम मोदी ने कहा कि 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए उसमें से करीब करीब

75%

मकान ऐसे हैं जिसका मालिकाना हक महिलाओं को मिला है।

एक महिला जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो जाती है। उसे क्या तकलीफ होती थी, ऐसे लोग समझ नहीं सकते हैं।

12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहन-बेटियों की मुश्किलें दूर की हैं।

- आजादी के 75 साल के बाद देश में करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास नल का कलेक्शन नहीं था। सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवार को घरों में नल से जल देने का काम किया है।
- मुस्लिम महिलाएं मुसीबत में जीने को मजबूर थीं, तीन तलाक का खात्मा कर संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक और समानता का अधिकार दिया है।

अर्थव्यवस्था-उद्योग की बात...

हमारे देश में एक नई अर्थव्यवस्था का समय-समय पर विस्तार होता रहा है। आज बड़े शहरों में गिग इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण एरिया डेवलप हो रहा है। एक अनुमान है कि आज देश में करीब-करीब एक करोड़ गिग वर्कर हैं और उस दिशा में भी काम कर रहे हैं।

अपार संभावनाओं भरे कदम

- इस बजट में कहा है कि ई-श्रम पोर्टल पर ऐसे गिग वर्कर अपनी रजिस्ट्री करवाए। ई-श्रम पोर्टल पर आने के बाद उन्हें एक आईडी कार्ड मिले। आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया जाएगा।
- एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यह छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं। नीति साफ है, एमएसएमई को सरलता, सहूलियत और संबल मिले।
- एमएसएमई सहित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पूरे इकोसिस्टम को बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मिशन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं।
- एमएसएमई क्षेत्र में सुधार के लिए क्राइटेरिया पिछले 10 वर्ष में दो बार अपग्रेड किया है। बिना किसी गारंटी के लोन दिया। छोटे उद्योग, उनके लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट गारंटी कवरेज की दिशा में कदम उठाए।

मध्यम वर्ग की बात पर...

देश के मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बीते 10 साल में इनकम टैक्स को कम करके भी मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाया है। नियो मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। एक बहुत बड़े हिस्से के टैक्स को इस बजट में जीरो कर दिया है। 2013 में दो लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, आज 12 लाख रुपये तक टैक्स में छूट दी है।

आकांक्षाओं का जिक्र, उपलब्धियों की बात

युवा सपनों पर बात...

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ा रोल देश के युवाओं का है जो अभी स्कूल कॉलेज में है। वही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी बनने वाले हैं। वो हमारा सामर्थ्य हैं। पिछले 10 साल में लगातार इस तबके को मजबूत करने के लिए सोची समझी रणनीति से काम कर रहे हैं। 21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, पहले सोचा तक नहीं गया। करीब तीन दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए जिसमें पीएम श्री स्कूल बन रहे हैं। आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या जो 10 वर्ष पहले 150 थे, आज 470 हो गए हैं।

उम्मीदों के संग न्याय

हमारा मॉडल... बचत से जनसेवा

पीएम मोदी ने कहा कि मैं बचत की तो बात कर रहा हूं लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपये बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। उन पैसों का उपयोग शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ जेम पोर्टल से जो खरीद हुई, वह कम पैसे में हुई। इससे सरकार के 1.15 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। बचे हुए पैसे का उपयोग देश बनाने के लिए किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 साल पहले 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये था जो 11 लाख करोड़ रुपये किया गया। योजनाएं ऐसी हो ताकि जनता को भी बचत हो। आयुष्मान भारत योजना का जिन लोगों ने लाभ लिया है, उससे भी जनता जनार्दन के 1.20 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। जन औषधि केंद्र से जिन परिवारों ने दवाइयां ली हैं, उनके करीब 30 हजार करोड़ रुपये दवाइयों का खर्चा बचा है। यूनिसेफ का भी अनुमान बताता है कि जिसके घर में शौचालय बने, उस परिवार को करीब करीब साल भर में 70,000 रुपये के बचत हुई है।

घोटालों पर तंज, सफलताओं पर बात

- पीएम ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नल से शुद्ध पानी मिलने के कारण उन परिवारों में जो अन्य बीमारियों के खर्चे होते थे, औसत 40 हजार रुपये परिवार का बचा है।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जहां-जहां यह योजना लागू हुई, उन परिवारों को औसतन साल भर के 25 से 30 हजार रुपये बिजली के पैसों में बचत हो रही है।
- जिन किसानों ने सॉइल हेल्थ कार्ड का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया है, ऐसे किसानों को प्रति एकड़ 30 हजार रुपये की बचत हुई है।
- एलईडी को बढ़ावा देने वाली योजना के कारण बिजली की भी बचत हुई और उजाला भी ज्यादा मिला। 20 हजार करोड़ रुपये बचे हैं देशवासियों के।

स्वच्छता प्रयासों के कारण, हाल के वर्षों में सरकार ने **2,300** करोड़ रुपये कमाए हैं सरकारी कार्यालयों से स्क्रैप बेचकर।

संविधान पर आस्था...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान में जो धाराएं हैं, उसके साथ-साथ संविधान का एक स्पिरिट भी है और संविधान को मजबूती देने के लिए संविधान की भावना को जीना पड़ता है। मैं उदाहरणों के साथ बताना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं जो संविधान को जीते हैं। संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें मजबूत और जनहितैषी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। पीएम ने कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के गोल्डन जुबली पर 50 साल में राज्यपाल के जितने भी भाषण हुए उन्हें ग्रंथ के रूप में तैयार कराया, क्योंकि हम संविधान की स्पिरिट को समझते हैं, उसे जीना जानते हैं। वर्ष 2014 में जब हम केंद्र में आए तो मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं था, तय किया कि जो सबसे बड़े दल का नेता है उसे बुलाएंगे। यह संविधान जीने का स्वभाव और लोकतंत्र का स्पीरिट होता है।

लोकतंत्र का सम्मान

विपक्ष को खरी-खरी

पीएम मोदी ने कहा दिल्ली में कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बनाकर रखे हुए हैं। जनता-जनार्दन के पैसों से काम हो रहा है। लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है, संविधान को जीना किसे कहते हैं, पीएम म्यूजियम बनाया। देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभभाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हैं। सात दशक तक जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को जेब में लेकर जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। तीन तलाक का खात्मा कर मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है। यह कांग्रेस है जिसने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थीं। जब देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी। जो बैठे थे महाशय, उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला, और दुनिया में डेमोक्रेट का टैग लगाकर घूमते रहे। मैं इमरजेंसी के उन दिनों को भूल नहीं सकता और शायद आज भी वो तस्वीरें मौजूद हैं। ■

विकसित भारत के संकल्प में देश का ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण

विकास को बढ़ावा देने के साथ प्रकृति को समृद्ध कर रहा भारत

किसी देश के लिए विकासशील से विकसित राष्ट्र तक की यात्रा में ऊर्जा क्षेत्र अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया जब अभूतपूर्व ऊर्जा संकट के दौर में है, विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे भारत के लिए यह क्षेत्र सबसे अहम प्राथमिकताओं में शामिल है। दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र कर विकास को बढ़ावा देने के साथ प्रकृति को समृद्ध करने की दिशा में दोहराई भारत की प्रतिबद्धता...

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बीते दशक में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं तो इसका श्रेय केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को है जिसके रास्ते पर चलकर भारत जी20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बना। भारत ने नवंबर, 2021 में ही गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसके साथ ही साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के नए लक्ष्य के तहत 200 गीगावाट की क्षमता भी हासिल कर ली है। अपने संबोधन में भारत की इन उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षा पांच स्तंभों पर टिकी है। हमारे पास संसाधन हैं, जिसका हम जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने प्रतिभाशाली दिमाग को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे पास आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता है। भारत के पास सामरिक भूगोल है, जो ऊर्जा व्यापार को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है।

उपलब्धियां... जिन्होंने बढ़ाया मान

- पेरिस जी20 के लक्ष्य को हासिल करने वाला भारत पहला देश है।
- आज भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है।
- पिछले 10 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ी है।
- पीएम सूर्य घर जैसी योजना के जरिए देश के सामान्य परिवारों और किसानों को ऊर्जादाता बनाया गया है। इससे सोलर सेक्टर में नई स्किल्स बन रही हैं, नया सर्विस इकोसिस्टम बन रहा है।
- भारत में अभी इथेनॉल मिश्रण की दर 19% है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत के साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। इस साल भारत 20% इथेनॉल मिश्रण दर को हासिल करने का प्रयास कर रहा है।
- भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बना, जो लगातार बड़ा हो रहा है। 28 राष्ट्र और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन जुड़ चुके हैं। ये कचरे को धन में बदलने का काम कर रहा है।

लक्ष्य... जो 5 साल में और बदलेंगे तस्वीर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए अगले दो दशक बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगले 5 वर्षों में हम कई बड़े मील के पत्थर पार करने जा रहे हैं। हमारे कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं।

- भारत की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई है और देश अब 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
- रेलवे के लिए 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना।
- सालाना पांच मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना शामिल है।
- भारत वर्तमान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है और अपनी क्षमता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

- सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरी के निर्माण से संबंधित कई वस्तुओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी है।
- पिछले 10 वर्ष में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2 गीगावाट से बढ़कर लगभग 70 गीगावाट हो गई है।

> दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की है। भारत न केवल अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि दुनिया के विकास को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

ऊर्जा संरक्षण में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन

ऊर्जा संरक्षण के मामले में भारत का प्रदर्शन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे बेहतर है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2010-19 के दौरान वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 2% का सुधार हुआ, जबकि भारत में यह 2.5% रहा। 2021-24 के दौरान वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 1.3% का सुधार हुआ, जबकि भारत की ऊर्जा तीव्रता में 1.6% का सुधार हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के तलछटीय बेसिन में कई हाइड्रोकार्बन संसाधन हैं, जिनमें से कुछ की पहचान पहले ही हो चुकी है, जबकि अन्य की खोज की जा रही है। भारत के अपस्ट्रीम क्षेत्र को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी शुरू की है। तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास अधिनियम में किए गए बदलावों से अब हितधारकों को नीतिगत स्थिरता, विस्तारित पट्टे और बेहतर वित्तीय शर्तें मिल रही हैं। इन सुधारों से समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस संसाधनों की खोज, उत्पादन में वृद्धि और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को बनाए रखने में सुविधा होगी। इससे निकट भविष्य में प्राकृतिक गैस के उपयोग में वृद्धि होगी। ■

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन

सुलभता और समावेशिता को बढ़ावा

एक विद्यार्थी अपने राष्ट्र की उस रीढ़ के समान है, जिस पर उसका भविष्य टिका होता है। ऐसे समय जब पूरी दुनिया ज्ञान के परिदृश्य में परिवर्तन के दौर से गुजर रही हो, रट कर की गई पढ़ाई की बजाय कौशल के साथ शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। वर्ष 2020 में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर लागू की गई। इसके साथ ही शुरूआत हुई एक नए अध्याय की, जिसने न केवल छात्रों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि उनके समग्र विकास को भी किया सुनिश्चित ...

भारत विकसित होने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसे पूरा करने की दिशा में सबसे ज्यादा जरूरत जीवन के हर कौशल से परिपूर्ण युवाओं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी मंत्र के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में सुदृढ़ आधारभूत शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दृष्टिकोण का मकसद पहले की कमियों में सुधार लाकर ऐसे वातावरण निर्मित करना है, जहां हर बच्चे का पूर्ण विकास हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य विशेषकर वंचित छात्रों के लिए शैक्षिक विषमताओं के चक्र को तोड़ना है। एनईपी लागू होने के बाद से अब तक इसके परिणाम भी बेहद सुखद रहे हैं। इसी का नतीजा है कि तेजी के साथ बदल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत आज शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ते हुए कुशल और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में खुद को ढाल रहा है। राष्ट्रीय

निजी की तुलना में सरकारी स्कूलों में बुनियादी कौशल में हुई तेज प्रगति

- 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन वर्ष 2024 में 98.1 प्रतिशत रहा जो पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक है।
- 2024 में कक्षा-1 में कम उम्र के बच्चों की संख्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नीति के अनुरूप 16.7 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर है।

शिक्षा के क्षेत्र में इस परिवर्तन को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान निपुण भारत मिशन का भी रहा है। इसके तहत किए गए उपायों के बेहतरीन परिणाम मिले हैं। जानिए किन लक्ष्यों के साथ शुरू हुई परिवर्तन की यात्रा...

स्पष्ट लक्ष्य: विशिष्ट बुनियादी कौशल हासिल करने पर ध्यान केंद्रित।

अभिनव शिक्षाशास्त्र: शिक्षा के प्रति आकर्षण जगाने के लिए खिलौनों की सहायता से जानकारी और प्रयोगात्मक शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना।

ग्रामीण प्रभावशीलता: शिक्षा के पारंपरिक साधनों की कमी को पाटना।

शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों को संदर्भ-विशिष्ट, प्रभावी शिक्षण रणनीतियों से युक्त बनाने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।

कदम दर कदम बेहतर मिला परिणाम

प्री-प्राइमरी नामांकन में निरंतर वृद्धि

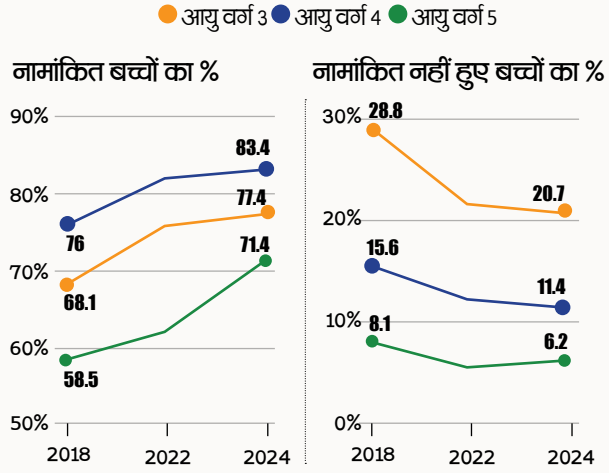

स्रोतः वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2024

70% से अधिक पहुंच गया है 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों में प्री स्कूल स्तर पर नामांकन, यह महत्वपूर्ण सुधार है।

- यह सुनिश्चित करता है कि किसी न किसी प्रारूप में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए सुलभ है, यह एक महत्वपूर्ण रूझान है।
- महामारी के बाद नामांकन दर में स्थिरता आई है और वर्ष 2018 से 2024 के बीच 3 से 5 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या भी कम हुई है।

शिक्षा नीति की सफलता का आकलन बेहतर नामांकन और ज्ञान सक्षमता के साथ कुशल कार्यबल के आधार पर किया जा सकता है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) सर्वेक्षण परिणाम में भी यह सामने आया है। राष्ट्रव्यापी स्तर पर घरों में किए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में बच्चों के नामांकन और सीखने के परिणाम सामने आए हैं।

बुनियादी कौशल में बढ़ोतरी

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 में कोविड के पहले और उसके बाद की स्थिति को बेहद बारीकी से बताया गया है। इसके अनुसार, हमारी प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के छात्र कोविड के दौर से पहले की तुलना में इस कालखंड से उबरने के बाद बुनियादी कौशल के मामले कहीं बेहतर साबित हुए हैं।

बेहतर बचपन की ओर

आंगनबाड़ी का नेतृत्व प्रारंभिक शिक्षा की रीढ़

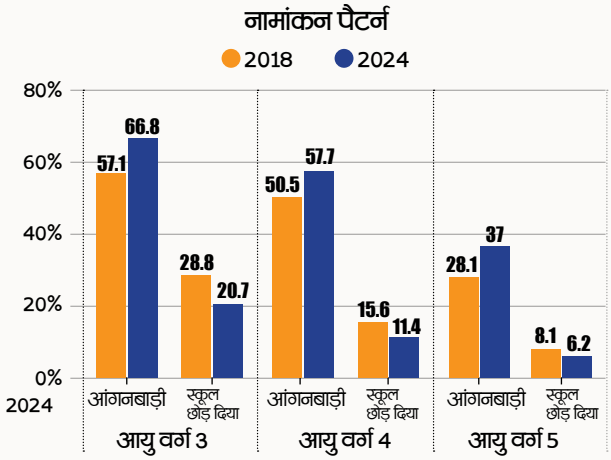

स्रोतः वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2024

माता-पिता के लिए आंगनबाड़ी उनके बच्चे के जरूरी विकास की दिशा में पहला और प्रत्यक्ष कदम होता है। यहां बच्चों को पोषण और टीकाकरण की सुविधा भी मिलती है। एनईपी के तहत अधिक आंगनबाड़ी वाले राज्यों में नामांकन अधिक होने से आरंभिक बाल विकास सुदृढ़ हुआ है।

स्मार्ट और सुरक्षित शिक्षा

अब डिजिटल साक्षरता को अपना रहे हैं किशोर

किशोर 14-16 वर्षों के

पहुंच

90% लड़के-लड़कियों के घर में स्मार्टफोन है

डिजिटल सुरक्षा

55% से अधिक लोग सुरक्षा पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं

76% सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करते हैं

उपयोग

82% जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है

57% इसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए करते हैं

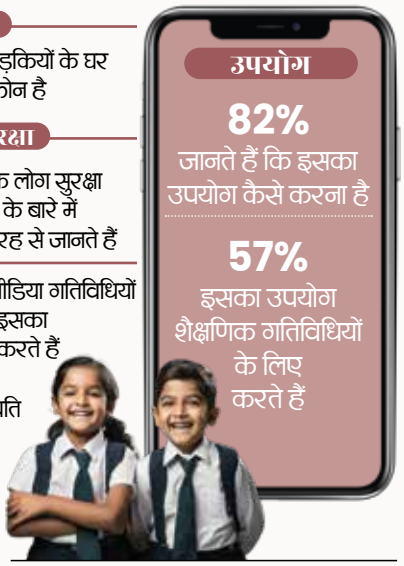

स्रोतः वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2024

- वे शिक्षा से संबंधित ऑनलाइन जानकारी खोजने में सहज हैं और उन्हें सुरक्षा विशेषताओं की भी जानकारी है।

मजबूत हुए स्कूल

बुनियादी ढांचा सुधार में प्रगति

- महामारी उपरांत स्कूलों में साफ-सफाई और स्वच्छता में सुधार।
- विद्यालयों में बेहतर बुनियादी ढांचे और उन्नत कक्षा के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है। शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर जुड़ाव को बढ़ावा मिला है। इससे सीखने के परिणाम में भी सुधार हुआ है।

डबल इंजन राज्यों

में उल्लेखनीय प्रदर्शन

- उत्तर प्रदेश में गत 20 वर्ष में साक्षरता और पठन-पाठन कौशल में जबरदस्त सुधार हुआ है।
- मध्य प्रदेश में 2024 तक स्कूलों में बिजली की पहुंच लगभग 90% तक बढ़ने से साक्षरता और संख्या में भी काफी प्रगति हुई है।
- गुजरात में भी बुनियादी स्तर पर शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन दिखा है।

शिक्षा के क्षेत्र में इन परिणामों से भारत प्रगति के पथ पर तीव्रता से बढ़ने में सक्षम हुआ है। अगले 5 वर्ष में वंचित बच्चों को दी गई यह सहायता अगले 25 वर्ष के लिए देश की दिशा-दशा तय करेगी। महामारी के बाद स्कूलों के फिर से खुलने से सभी राज्यों में शैक्षणिक स्तर पर अथक प्रयास हुए हैं, जिससे बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने, समावेशिता और बुनियादी शिक्षा के सुपरिणाम सामने आए हैं।

चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बच्चों को स्कूल में रखने का दृढ़ संकल्प प्रभावी सरकारी नीतियों को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि निपुण भारत मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक योजना भर नहीं है, बल्कि ये सीखने की कमियों को दूर करने के साथ 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत की मानव संसाधन पूंजी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुरक्षित बनाने का रणनीतिक निवेश है। ■

अमेरिका-फ्रांस दौरा

मेक इंडिया ग्रेट अगेन

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जब 13 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थीं। ऐसे समय जब कई देश अमेरिका के कई फैसलों से भारी उथल-पुथल का सामना कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ मेक इंडिया ग्रेट अगेन को जोड़ते हुए नेशन फर्स्ट को सबसे आगे रखा तो दोनों देशों के रिश्तों की गर्मजोशी भी आपसी बातचीत के मुद्दों से लेकर साझा बयान तक दिखी...

भारत अपने यथार्थवाद की उस नीति पर चल रहा है, जहां किसी क्षेत्रीय या फिर वैश्विक लक्ष्य के लिए सिर्फ हितों के आधार पर रिश्ते बनाने की बजाय उसके हित से जुड़े मूल्यों के आधार पर संतुलित होते हैं। खासतौर पर ऐसे मूल्य जो एक ऐसी उभरती शक्ति के हैं, जिसके इरादे विस्तारवादी होने की बजाय समानता के भाव के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर उसकी भूमिका को बढ़ाते हैं। दुनिया में भारत की इस बदली हुई भूमिका के कारण ही अमेरिका के साथ उसके संबंध समय के साथ और मजबूत हुए हैं। हिंद-प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी से लेकर व्यापार, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी रुख, ऊर्जा समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों देशों की करीबी दुनिया के सामने है। रिश्तों में इसी मजबूती की मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान भी दिखाई दी, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'मैंने आपको बहुत याद किया।' राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को 'एक शानदार दोस्त' और 'एक अद्भुत व्यक्ति' भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस में पहले कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों के बढ़ते दायरे को याद कर उन्हें दूसरे कार्यकाल की बधाई दी। साथ ही, कहा कि अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) से परिचित हैं। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर हैं। विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी MIGA है। भारत और अमेरिका जब साथ काम करते हैं, तो MAGA+MIGA बन जाता है MEGA पार्टनरशिप। मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉसपैरिटी और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्पेस देती है। बैठक में बहुपक्षीय सहयोग और अवैध प्रवासी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने 'यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट' की भी शुरुआत की, जिसका मतलब है, सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को बढ़ावा देना।

ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में अहम कदम

अमेरिका ने भारत को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अपना दृढ़ समर्थन दिया। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में ऊर्जा व्यापार बढ़ाने, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। भारत और अमेरिका ने 123 असैन्य परमाणु समझौते को पूरी तरह से साकार करने की घोषणा की।

- भारत का प्रमुख तेल और गैस आपूर्तिकर्ता बनेगा अमेरिका।
- भारत में अमेरिकी परमाणु उद्योग को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन।
- भारत में अमेरिकी परमाणु तकनीक के स्वागत के लिए कानूनों में सुधार।

व्यापार और निवेश में बढ़ेगा सहयोग

भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक साहसिक निर्णय लिया है। 'मिशन 500' के तहत वर्ष 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार दोगुना से अधिक करके 500 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य तय किया गया है। अमेरिका ने बोरबॉन, मोटरसाइकिल, आईसीटी उत्पादों और धातुओं के क्षेत्र में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ अमेरिकी कृषि उत्पादों के बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए भारत के फैसले का स्वागत किया है। भारत के आम और अनार का निर्यात बढ़े इसके लिए अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों की भारत ने सरहाना की।

रक्षा संबंधों के लिए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क

- रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाने एवं इस वर्ष 21वीं सदी में यूएस-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क की घोषणा की।
- भारत की रक्षा आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने के एंटी टैंक गाइडेड मिसाल जेवलिन और इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन स्ट्राइकर सह निर्माण पर काम किया जाएगा।
- हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री निगरानी के लिए छह अतिरिक्त पी-8आई समुद्री गश्ती विमानों की खरीद हो सकेगी।

भारत के लिए एफ-35 स्टील्थ फाइटर हासिल करने का रास्ता साफ।

अमेरिका से भारत को होगी अरबों डॉलर की सैन्य आपूर्ति।

दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मार्ग इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर पर भी बात

- भारत और अमेरिका मिलकर इस ऐतिहासिक व्यापार मार्ग को बनाएंगे।
- यह मार्ग भारत, इजराइल, इटली और अमेरिका को जोड़ेगा।
- सड़क, रेल मार्ग और समुद्र के नीचे केबल्स का होगा एकीकरण।
- आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा बड़ा बढ़ावा।

अवैध अप्रवासियों पर मिलकर करेंगे काम

अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले सत्यापित भारतीय नागरिक को भारत वापस लेने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत से जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका आए हैं, वह सामान्य परिवारों से हैं। यह मानव तस्करी का भी मामला है। लिहाजा इसमें भारत और अमेरिका को मिल कर काम करना होगा और इसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा।

अमेरिका-भारत के रिश्ते हुए और प्रगाढ़

- लॉस एंजेलिस और बॉस्टन में जल्द खुलेंगे नए भारतीय वाणिज्य दूतावास।
- अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भारत में ऑफशोर कैंपस स्थापित करने का न्यौता।
- लोगों के बीच आपसी संबंधों को मिलेगा बढ़ावा।

स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका से हमारा करीबी सहयोग रहा है। इसरो और नासा के आपसी सहयोग से बनाई निसार सैटेलाइट शीघ्र ही भारतीय लॉन्च व्हीकल पर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी।

इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर मजबूत साझेदारी

दोनों देशों ने यूएस-इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी (ट्रस्ट), एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रोडमैप और इंडस इनोवेशन जैसी नई पहलों की घोषणा की। यह पहल सरकारी, अकादमिक और निजी क्षेत्र के सहयोग को मजबूत करेंगी, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायो टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों का विकास और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

आतंकवाद पर नकेल... तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी

दोनों देशों ने दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने का संकल्प लिया गया। 26/11 को मुंबई में हुए हमलों और 26 अगस्त, 2021 को अफगानिस्तान में एबी गेट बम विस्फोट जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अलकायदा, आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सहित आतंकवादी समूहों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। अमेरिका ने घोषणा की कि तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने भेंट की किताब, लिखा...

मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट

अपने अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ-साथ उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क से भी मुलाकात की।

- राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक किताब 'ऑवर जर्नी टुगेदर' भेंट की। 320 पन्नों की इस किताब में '2019 में हुए हाउडी मोदी' और '2020 में हुए नमस्ते ट्रंप' प्रोग्राम की तस्वीरें हैं। ट्रंप ने इस किताब पर संदेश लिखा- मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट।
- पीएम मोदी ने उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के बेटे इवान को मधुबनी लोक चित्रकला वाली एक पहेली, दूसरे बेटे विवेक को लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और बेटी मिराबेल रोज वेंस को लकड़ी का एल्फाबेट दिया।
- इलॉन मस्क ने पीएम मोदी को स्पेसएक्स की स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 5 का हीट शील्ड यानी कवच से बना मोमेंटो दिया। ये कवच अंतरिक्षयान को भीषण तापमान से बचाता है। वहीं, पीएम मोदी ने मस्क के बच्चों को रवींद्रनाथ टैगोर की द क्रिसेंट मून, द ग्रेट आरके नारायण कलेक्शन और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र किताब उपहार में दी।

भारत-फ्रांस का मजबूत होता रणनीतिक सहयोग

भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देश के संबंधों के मूल में रक्षा साझेदारी है। 26 जनवरी, 2025 को भारत-फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के 27 वर्ष पूरे हुए हैं। दोनों देश के बीच संबंध एवं सहयोग को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी छठी यात्रा पर पहुंचे। जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय संबंध, प्रमुख वैश्विक-क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के साथ ही रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक सहयोग की समीक्षा की।

भारत-फ्रांस के रणनीतिक संबंधों में रक्षा, सुरक्षा, असैन्य परमाणु मामले और अंतरिक्ष सहयोग के प्रमुख स्तंभ हैं। अब इसमें एक मजबूत भारत-प्रशांत घटक भी शामिल है। हाल के वर्षों में साझेदारी में समुद्री सुरक्षा, डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा और उन्नत कंप्यूटिंग, आतंकवाद का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय-सतत विकास और विकास भी शामिल है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने चर्चा के बाद स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा एवं लोगों के बीच आपसी संबंधों पर संतोष जताया है। साथ ही भारत-प्रशांत क्षेत्र, वैश्विक मंच एवं पहलों में आपसी जुड़ाव को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। दोनों देश के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय को अंतिम रूप दिया गया।

दोनों नेता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से समन्वय करने पर सहमति जताई। फ्रांस ने एक बार फिर से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को दोहराया। दोनों देश मार्च 2026 में नई दिल्ली में भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर मनाएंगे। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की। आतंकवाद के वित्तपोषण करने वाले

नौकरियों का नुकसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे भयावह पक्ष है लेकिन, इतिहास बताता है कि प्रौद्योगिकी के कारण काम खत्म नहीं होता है। इसकी प्रकृति बदलती है और नए प्रकार की नौकरियां पैदा होती हैं। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस -संचालित भविष्य के लिए अपने लोगों को कौशल और पुनः कौशल प्रदान करने में निवेश करने की जरूरत है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

फ्रांसीसी कंपनियों को पीएम का न्योता

पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पेरिस में 14वें भारत-फ्रांस सीईओ फोरम को संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने फोरम में आए फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ को भारत आने का निमंत्रण देते हुए कई उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का जिक्र करते हुए फ्रांसीसी कंपनियों से भारत के साथ साझेदारी करने का आह्वान किया है।

भारत करेगा अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी

भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फ्रांस के पेरिस में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन की सहअध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एआई ऐसी तकनीक है जो राजनीति, अर्थव्यवसथा, सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और समाज सहित कई क्षेत्रों में सुधार कर लाखों लोगों के जीवन को बदला जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी विविधता को देखते हुए एआई के लिए अपना स्वयं का वृहद् भाषा मॉडल बना रहा है।

नेटवर्क और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने पर सहमति बनी। इस बात पर भी सहमति बनी कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाह नहीं देनी चाहिए जो आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषण, समर्थन या अंजाम देते हैं। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के संबंध में भारत-फ्रांस ने असैन्य परमाणु संबंधों और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्रों में 13 मिलियन यूरो के इक्विटी साझेदारी का स्वागत किया। द्विपक्षीय बैठक में भारत और फ्रांस के बीच 1966 में हुए प्रथम सांस्कृतिक समझौते की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वर्ष 2026 में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने पर सहमति भी जताई गई। इसके साथ ही 2030 तक फ्रांस में 30 हजार भारतीय छात्र के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बेहतर माहौल बनाया जाएगा। 2025 में इस संख्या के 10,000 तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत टेक्स

विकसित भारत की संभावनाओं का दर्शन

पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, भारत में पारंपरिक परिधानों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। आज भारत 3 लाख करोड़ रुपये तक के कपड़ा और परिधानों का निर्यात कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है तो अब वर्ष 2030 तक इसे 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का रखा है लक्ष्य। इसमें 14-17 फरवरी तक राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स- 2025 जैसे वैश्विक आयोजन ने दी है मजबूती, जिसमें 120 से अधिक देशों ने की शिरकत...

भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में टेक्सटाइल सेक्टर 2 फीसदी से ज्यादा का योगदान देता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद यह 4.5 करोड़ श्रमबल के साथ रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर भी है। दुनिया के टेक्सटाइल और परिधान बाजार में 37 अरब डॉलर के निर्यात के साथ भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 4.5 फीसदी है। सफलता के इन आंकड़ों के पीछे एक दशक की वो मेहनत और नीतियां भी हैं, जिनके रास्ते भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर ने इस बुलंदी को छुआ है। 'भारत टेक्स 2025' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ एक दशक की इस यात्रा का जिक्र किया, बल्कि नई सोच और नए प्रण के साथ इस सेक्टर को और आगे ले जाने का अपना संकल्प भी दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश दोगुना हुआ है। टेक्सटाइल देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर देने वाली उद्यमों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब इस सेक्टर में निवेश आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो उसका फायदा टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों को भी मिल रहा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग में यह सेक्टर 11 फीसदी का योगदान दे रहा है। यही कारण है कि सरकार ने इस बार के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है।

5 एफ से ग्रोथ के नए रास्ते तक

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले साल भारत टेक्स में मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन जैसे 5एफ फैक्टर्स की बात की थी। ये विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है।

भारत के टेक्सटाइल उद्योग के लिए सबसे बड़ा मंच

देश के टेक्सटाइल सेक्टर के सबसे बड़े वैश्विक आयोजन के रूप में बीते वर्ष से हर साल भारत टेक्स का आयोजन किया जा रहा है। इस बार नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजन 14 से 17 फरवरी तक हुआ। इसके जरिए कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक स्थान, एक मंच पर लाया गया। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन है, जिसमें दो स्थानों पर फैला एक मेगा एक्सपो शामिल है। पूरे कपड़ा इकोसिस्टम को प्रदर्शित करता है। भारत टेक्स 2025 में नीति निर्माता और वैश्विक सीईओ के साथ 5000 से अधिक प्रदर्शक, 120 से अधिक देश के 6,000 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने हिस्सा लिया।

तकनीक के साथ हाथ को हुनर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी सेक्टर तभी आगे बढ़ता है, जब उसके लिए हुनरमंद श्रमबल उपलब्ध हो। वस्त्र उद्योग में तो सबसे बड़ा रोल ही स्किल यानी हुनर का होता है। इसीलिए हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हुनरमंद प्रतिभा का एक पूल बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हैंडलूम की विश्वसनीयता और हाथ के कौशल को भी उतना ही महत्व मिले। हथकरघा कारीगरों का हुनर दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, उनकी क्षमता बढ़े, उन्हें नए अवसर मिलें। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए 2,400 से ज्यादा बड़े मार्केटिंग इवेंट का आयोजन किया गया। हैंडलूम उप्तादों की ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए **India-hand-made** नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है।

दूरदर्शी दृष्टिकोण पर जोर

टेक्सटाइल सेक्टर की समस्याओं का समाधान और संभावनाओं के सृजन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके लिए हम दूरदर्शी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। दुनिया के कॉटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी मजबूत हो, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बने इसके लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन का ऐलान किया है।

उभरते सेक्टर पर फोकस

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा फोकस टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे टेक्सटाइल क्षेत्र के उभरते सेक्टरों पर है। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो टेक्सटाइल कारोबारियों से मिलना-जुलना होता था। उस समय जब मैं उनको टेक्निकल टेक्सटाइल की बातें करता था, तो वो मुझे पूछते थे, आप क्या चाहते हैं, आज मुझे खुशी है कि भारत इसमें अपनी पहचान बना रहा है। हम स्वदेशी कार्बन फाइबर और उससे बने उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत उच्च श्रेणी का कार्बन फाइबर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इन प्रयासों के साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो नीतिगत फैसले होने चाहिए, हम वो भी ले रहे हैं।

खादी फॉर नेशन से खादी फॉर फैशन

पीएम मोदी ने कहा कि पहले दुनिया के और देश हमें कहते थे काला पहनो, हम पहन लेते थे। अब हम दुनिया को कहेंगे, क्या पहनना है। इसीलिए आज एक ओर पारंपरिक खादी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही एआई के जरिए फैशन के ट्रेंड्स का भी विश्लेषण किया जा रहा है। आज खादी जिस प्रकार से प्रगति कर रही है और दुनिया के लोगों का आकर्षण का कारण बन रही है। हमें इसको और बढ़ावा देना चाहिए। पहले जब आजादी का आंदोलन चला, तब खादी फोर नेशन था, अब खादी फोर फैशन होना चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि सैकड़ों वर्ष पहले जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, उस समृद्धि में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज जब हम विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर टेक्सटाइल सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। भारत टेक्स जैसे आयोजन इस सेक्टर में भारत की स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। मुझे विश्वास है, ये आयोजन इसी तरह हर वर्ष सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। ■

ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने कहा

विकसित भारत की असली नींव है विश्वास

औपनिवेशिक काल की मानसिकता से मुक्ति दिलाकर न्याय में तेजी लाना हो या गांवों में संपत्ति विवाद को खत्म कर आपसी विश्वास को बढ़ाना, प्रगति की राह में छूटे आकांक्षी जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम हो या बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त कर गांव-गरीब तक पहुंचना। 'फियर ऑफ बिजनेस' को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में बदलना हो या औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए देश को तैयार करना और विकसित भारत की यात्रा में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना। एक दशक के प्रदर्शन से केंद्र सरकार ने 'विश्वास' को नागरिक-सरकार-कारोबारी सभी कि लिए बना दिया है आवश्यक...

भारत आज वैश्विक मंच पर पहले से ज्यादा मजबूत और विश्वासभरा नजर आ रहा है तो इसके पीछे रिफॉर्म के रूप में वह कदम भी हैं, जिन्होंने सुधारों की एक नई क्रांति को जन्म दिया है। तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में जनता का विश्वास ही महत्वपूर्ण कारक रहा है। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते एक दशक की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सोचिए यह रिफॉर्म अगर नहीं हुए होते तो क्या इतने सारे बदलाव लाए जा सकते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तो कांग्रेस के समय भी चल रहा था, लेकिन विकास की रफ्तार और भ्रष्टाचार की रफ्तार देश देख रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि अगर वही जारी रहता तो देश का अहम कालखंड नष्ट हो गया होता।

देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक रफ्तार की दिशा एवं दशा पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक की अपनी यात्रा के कई अहम मुद्दों और उसके परिणामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 में तो कांग्रेस सरकार यह लक्ष्य लेकर चल रही थी कि 2044 में भारत को 11वीं से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 30 साल का समय... ये तब विकास की रफ्तार थी। अब देख सकते हैं कि सिर्फ एक दशक में भारत दुनिया की शीर्ष 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। उनका कहना था, "मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखेंगे।"

एनपीए को पीछे छोड़ आज बैंक सवा लाख करोड़ के लाभ में

बैंकिंग सेक्टर में किए गए रिफॉर्म का खाका सबके सामने रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले ये तर्क दिया जाता था कि देश में बैंक ब्रांच नहीं है, तो कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा? आज देश के करीब-करीब हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरसपॉन्डेंट मौजूद है। एमएसएमई के लिए लोन मिलना आज बहुत आसान हुआ है। आज रेहड़ी-पटरी ठेले वालों तक को आसान लोन से जोड़ा है। किसानों को मिलने वाला लोन भी दोगुने से अधिक किया है। 10 साल पहले तक बैंकों के रिकॉर्ड घोटाले और एनपीए की खबरें छपती थीं। आज अप्रैल से दिसंबर तक सरकारी बैंकों ने सवा लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है।

'फियर ऑफ बिजनेस' की जगह अब 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते दशक में 'फियर ऑफ बिजनेस' की जगह अब 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' ने ली है। जीएसटी के कारण, देश में जो एक बाजार की व्यवस्था बनी है, उससे भी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिल रहा है। बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। इससे देश में लॉजिस्टिक लागत घट रही है, क्षमता बढ़ रही है। सैकड़ों अनुपालन खत्म किए और अब जन विश्वास 2.0 से और भी अनुपालन को कम कर रहे हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि समाज में सरकार का दखल और कम होना चाहिए, इसके लिए सरकार एक आयोग भी बनाने जा रही है।

अब प्रदर्शन पर आधारित राजनीति का वक्त

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारी राजनीति परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो चुकी है। अब भारत की जनता ने दो टूक कह दिया है- टिकेगा वही, जो जमीन से जुड़ा रहेगा, जमीन पर रिजल्ट लाकर दिखाएगा। इसलिए सरकार को लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है।

रिफॉर्म का जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि पहले वे रिफॉर्म होते थे, जिन्हें करने की मजबूरी होती थी। आज रिफॉर्म दृढ़ विश्वास से हो रहे हैं। देर से मिला न्याय, न्याय नहीं है...जैसी बातें हम लंबे समय तक सुनते रहे लेकिन इसे ठीक कैसे किया जाए, इस पर बात ही नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ समय पहले तक जो पीनल कोड चल रहे थे, वो 1860 के बने थे। हमें गुलामी की मानसिकता में जीने की आदत हो गई थी। जिस सिस्टम के मूल में ही दंड है, वहां न्याय कैसे मिल सकता था। इसलिए इस सिस्टम के कारण न्याय मिलने में कई-कई साल लग जाते थे। हमने भारतीय न्याय संहिता के साथ इसे बदला। इसके पीछे कड़ी मेहनत थी।

पीएम मोदी ने कहा कि यूएन की एक स्टडी में किसी देश के लोगों के पास संपत्ति के अधिकार का न होना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया है। भारत में भी यही हालत थी लेकिन कौन इतना सिरदर्द उठाता। इसके लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इसके तहत देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों का ड्रोन सर्वे किया गया। सवा 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को संपत्ति कार्ड दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जिलों को पिछड़ा मानकर छोड़ दिया गया था। हमने उन्हें आकांक्षी जिला माना। ऐसे 100 जिलों के 500 ब्लॉक्स को आकांक्षी घोषित किया और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में सफल रहे।

सम्मेलन में आए तमाम उद्योगपतियों से आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की असली नींव विश्वास पर टिकी है। हर देशवासी, हर सरकार, हर बिजनेस लीडर में ये एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से देशवासियों में विश्वास बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। कारोबार से लेकर नव उद्यमियों के हित तक सरकार अपनी तरफ इस दिशा में काम कर रही है।

कौशल भारत कार्यक्रम दो साल का मिला विस्तार

दुनियाभर में मांग बढ़ने के साथ-साथ कुशल श्रमबल पहली शर्त है। यही कारण है कि देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए 2014 में पहली बार किसी सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया। अब तक 2.27 करोड़ से अधिक युवा कौशल भारत कार्यक्रम का लाभ ले चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने इसे 2026 तक बढ़ाने को दी मंजूरी...

निर्णय : कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन।

प्रभाव : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया यानी कौशल विकास कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। इसके पुनर्गठन के लिए 8,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना को अब 'स्किल इंडिया कार्यक्रम' की समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जोड़ दिया है। इससे देशभर में कुशल, मांग पर आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम उद्योगों के लिहाज से भविष्य के लिए श्रमबल तैयार करने में मदद मिलेगी।

निर्णय : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल अब 31 मार्च 2028 तक।

प्रभाव : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाने, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और सफाई का खतरनाक काम करते समय शून्य मृत्यु दर की स्थिति में पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए करीब 50.91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 को सितंबर, 1993 में अधिनियमित किया गया था। एक वैधानिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन पहली बार अगस्त, 1994 में किया गया था।

निर्णय : विशाखापत्तनम में प्रस्तावित साउथ कोस्ट रेलवे जोन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी।

प्रभाव : इस जोन में वाल्टेयर डिवीजन को छोटा करके शामिल किया गया है। यह रेलवे का 18वां जोन होगा। रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। यह फैसला आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया है। यह संसद की ओर से की गई प्रतिबद्धता को भी पूरा करता है। इस जोन से रेलवे का कामकाज सुधरेगा। सेवाएं बेहतर होंगी और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। ■

PMO India
@PMOIndia

Our Government has worked to create maximum opportunities for people from SC, ST and OBC Communities.

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India
@DefenceMinIndia

Aero India 2025 का समापन हो रहा है। परन्तु मैं समझता हूं, कि Aero India जैसे Exhibitions का Physically भले ही समापन हो जाए, लेकिन इसका Impact कभी खत्म नहीं होता। यह समारोह भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन यह जिस तरह से देश-विदेश के Participants को एक साथ जोड़ रहा है, जिस तरह से Public-private Sector के Collaboration को Ensure कर रहा है, जिस तरह से नई Generations को Inspire कर रहा है, मुझे लगता है, इसका Impact बहुत लंबे समय तक रहेगा: रक्षा मंत्री

Amit Shah
@AmitShah

नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गयी है।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

Triumph for India! 🏏🏆

Heartiest congratulations to the Indian Women's Cricket Team for their phenomenal T20 #U19WorldCup victory! 🇮🇳

An inspiring showcase of grit, unity, and relentless spirit. The entire nation beams with pride! 👏

Shandilya Giriraj Singh
@girirajsinghbjp

BharatTex2025 जहाँ फैब्रिक से फ्यूचर तक, ट्रेड, ट्रेडिशन और टैक्नोलॉजी का महासंगम होगा! मेक इन इंडिया की ताकत, वोकल फॉर लोकल का संकल्प और सस्टेनेबिलिटी की नई लहर के साथ पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगी! 14 से 17 फरवरी तक आयोजित भारत के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल महाकुंभ का हिस्सा बनें और टेक्सटाइल उद्योग की नई उड़ान के साक्षी बनें!

Jyotiraditya M. Scindia
@JM_Scindia

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने आदिवासी समाज के केवल गांव नहीं बल्कि घर-घर के समावेशी विकास की भी योजना बनायी है।

विश्व वन्यजीव दिवस

विविधता का उत्सव

3 मार्च

106 राष्ट्रीय उद्यान **573** अभयारण्य

- 343 संरक्षित और कम्युनिटी रिजर्व
- 1,78,640.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र

▪22 लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण और पुनर्वास

▪हंपबैक व्हेल ▪हिम तेंदुआ ▪हंगुल ▪संगाई हिरण ▪समुद्री कछुआ ▪बस्टर्ड ▪लाल पांडा ▪निकोबार मेगापोड ▪जेडर्न कोरसर▪ काराकल सहित 22 जीव हैं।

> विश्व वन्यजीव दिवस पर सभी पशु प्रेमियों को बधाई। आज का दिन अपनी धरती पर जीवों की अविश्वसनीय विविधता का उत्सव मनाने और इनकी रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। मैं उन सबकी भी सराहना करता हूं जो वन्यजीव संरक्षण के लिए सतत प्रयासों में सबसे आगे हैं और इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 मार्च, 2025

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 26-28 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 18 फरवरी 2025, कुल पृष्ठ-48)

प्रधान संपादक: धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक: योगेश कुमार बवेजा, महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020